

आम आदमी[®]

एक आम इंसान की सोच



छत्तीसगढ़ सरकार के
4 साल
CM बघेल ने
गिनाई उपलब्धियां

नये साल में
सीएम भूपेश बघेल
ने दी 4 बड़ी सौगातें

प्रधानमंत्री ने
छत्तीसगढ़ के मिलेट
मिशन को सराहा

जए साल की वो
5 उम्मीदें जो सपनों
को देंगी उड़ान

21 साल बाट भारत
की सरगन
बनी मिसेज वर्ल्ड



Taste Our Delicious Food at your Doorstep!

Order on





प्रबंध संपादक	: उमेश के बंसी
सर्कुलेशन इंचार्ज	: प्रकाश बंसी
रिपोर्टर	: नेहा श्रीवास्तव
फॉटो राईटर	: प्रशांत पारीक
क्रिएटिव डिजाइनर	: देवेन्द्र देवांगन
मैगजीन डिजाइनर	: युनिक ग्राफिक्स
मार्केटिंग मैनेजर	: किरण नायक
एडमिनिस्ट्रेशन	: निरुपमा मिश्रा
अकाउंट असिस्टेंट	: प्रियंका सिंह
ऑफिस कॉर्डिनेटर	: योगेन्द्र विसेन

प्रधान कार्यालय

965/1 ककड़ चौक, श्याम नगर रोड,
कटोरा तालाब, रायपुर, छत्तीसगढ़

फोन : 0771-4044047

ईल : khabar@aamaadmi.in

कार्यालय

प्लाट नं.118, कंचन बाग, राजनांदगांव

प्रकाशक

उमेश कुमार बंसी, वाटर नंबर 10, एम.एम.
रियल स्टेट कॉलोनी, अमलीडीह, रायपुर
(छत्तीसगढ़) से प्रकाशित एवं मुद्रित

विशेष- इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में दिये गए
विचार, लेखकों के अपने हैं। इसमें संपादक / मुद्रक की
सहमति अनिवार्य नहीं है। किसी भी प्रकार के विवाद
की स्थिति में संपादक / मुद्रक जिम्मेदार नहीं होगा। इस
पत्रिका से संबंधित किसी भी विवाद के लिए सुनवाई
क्षेत्र रायपुर न्यायालय होगा।

न्याय के चार साल : छत्तीसगढ़ में और बढ़ेगा बिजली का उत्पादन



रायपुर. छत्तीसगढ़ में ऊर्जा उत्पादन के इतिहास में एक मील का पत्थर और स्थापित हो गया जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 25 अगस्त को 1320 मेगावाट के नए पॉवर प्लांट लगाने का निर्णय लिया।

8-9



जहां रेल नहीं, वहां भी घर तक पहुंचेगा पार्सल

ट्रेन से पार्सल आने पर सीधे गोदाम में उतरेगा। इस पार्सल को डाक विभाग तकाल अपने कब्जे में लेगा।



29 साल बाद भारत की सरगम बनी मिसेज वर्ल्ड 14

भारत की सरगम कौशल को शनिवार को मिसेज वर्ल्ड 2022 चुना गया।



एनडीटीवी : मसला सिफ एक वैनल या पफकार का नहीं है

एनडीटीवी के जबरिया और टिकटमी टेकओवर पर देश भर में विशेष और चिंता की लहर सी उठी है।



राम सेतु मामला CM भूपेश बघेल ने कहा देश से माफी मांगे BJP 22

पौराणिक कथाओं के मूलाधिक भारत और श्रीलंका के बीच जो समुद्र में पुल बना है, वो रामसेरु हैं।



ग्रामोद्योग विभाग से ग्रामीण अंचल की महिलाओं और श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए दिया जा रहा प्रशिक्षण

ग्रामीण अंचल में रोजगार से सीधे जोड़ने का प्रयास कर रही है ग्रामोद्योग विभाग



राजभवन-राज्य सरकार के बीच बढ़ा तनाव, सीएम भूपेश ने लगाया बड़ा आरोप 36

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरक्षण संशोधन विधेयकों पर राज्यपाल की सहमति में कथित देरी को लेकर राजभवन की आलोचना की।

नोटबंदी के फैसले से देश को हुए फायदे



उमेश के बंसी
(प्रबंध संपादक)

सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के नवंबर 2016 के 1,000 और 500 रुपये के नोटों के विमुद्रीकरण के फैसले को वैध ठहराया है। माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले पर मुहर लगाने वाले इस फैसले से वर्षों से चल रहे विवाद पर विराम लग जाएगा।

गौरतलब है कि विरोधी दलों सहित कई अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री इस फैसले का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि सरकार के इस फैसले से आम जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और साथ ही, इससे छोटा-मोटा व्यवसाय करने वालों को भारी नुकसान हुआ। इससे उनका रोजगार भी प्रभावित हुआ। दूसरी ओर, देश में एक बड़ा वर्ग नोटबंदी के फैसले का समर्थन कर रहा था। सरकार का एक तर्क यह भी था कि नोटबंदी से काले धन पर आक्रमण होगा। हालांकि, नोटबंदी के बाद देश में अधिकांश नकदी, नए नोटों में तब्दील हो गई, लेकिन यह भी सच है कि नोटबंदी के बाद नगदी जो काले धन के रूप में कहीं न कहीं अनुपयुक्त पड़ी थी, बैंकिंग व्यवस्था में शामिल हो गई और उसका देश के विकास में इस्तेमाल संभव हो सका।

आम आदमी की मुश्किलों की बात करें, तो हमें समझना होगा कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, 92 प्रतिशत गृहस्थों में किसी भी सदस्य की अधिकतम आय अर्जित करने वाले सदस्य की आमदनी 10,000 रुपये मासिक से कम ही थी। ऐसे में, उन कम आय वाले लोगों के पास 500 और 1,000 रुपये के नोट बड़ी मात्रा में होने की संभावना बहुत कम थी। यही नहीं, तब तक बड़ी संख्या में (लगभग 32 करोड़) जन-धन खाते भी खुल चुके थे, जिसमें आसानी से पुराने नोट जमाकिए जा सकते थे। इसलिए आम आदमी को इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं था।

नोटबंदी का एक महत्वपूर्ण फायदा महंगाई पर अंकुश है। जाहिर है, बड़ी मात्रा में करेंसी के रूप में काला धन चंद अमीरों के पास क्रय शक्ति को बढ़ाता है, जिससे महंगाई बढ़ती है। नोटबंदी के बाद महंगाई में कमी देखी गई। दिसंबर 2016 से नवंबर 2022 के दौरान उपभोक्ता कीमत सूचकांक (उपभोक्ता महंगाई) में कुल 32.5 प्रतिशत की वृद्धि रिकार्ड की गई, जबकि इससे पूर्व के छह वर्षों में यह वृद्धि 54.1 प्रतिशत की थी। कहा जा सकता है कि डॉक्टर आंबेडकर की बात सही सिद्ध हो रही है कि विमुद्रीकरण महंगाई रोकने का एक कारगर माध्यम हो सकता है।

छत्तीसगढ़ सरकार के 4 साल CM बघेल ने गिनाई उपलब्धियां

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शासित भूपेश बघेल सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं। इस खास मौके को प्रदेश कांग्रेस पार्टी सभी जिलों में गौरव दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया। सीएम भूपेश बघेल ने एक तरफ इन 4 सालों की उपलब्धियां गिनाईं। वहीं, दूसरी तरफ मोदी सरकार पर तंज भी करा है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का बीजेपी दुरुपयोग कर रही है। बीजेपी लोगों का भावनात्मक शोषण कर रही है। हमारी सरकार ने हर वादे को प्रदेश में झीमानदारी से लागू किया है।



उपलब्धियां गिनाते हुए सीएम बघेल ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है। किसानों की आय में वृद्धि हुई है। छत्तीसगढ़ की कला को भारत में पहचान मिली है। कोरोना काल में भी सरकार ने लोगों की सेवा की है।

मीडिया से बातचीत में सीएम बघेल ने कहा कि एक बात तो साफ हो गई कि बीजेपी यह मान चुकी है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का मुकाबला नहीं कर सकती है। इसलिए बीजेपी ने केंद्रीय एजेंसियों को दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है। बघेल ने यह भी कहा कि जनता भी अब जान चुकी है कि छत्तीसगढ़ सरकार को सिर्फ बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आने वाले वर्त में जनता के लिए क्या खास होगा? सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हम लगातार समृद्ध रोजगार लाने के लिए लगे हैं।

केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के साथ कर रही सौतेला व्यवहार

बीजेपी भावनात्मक शोषण करती है। गाय और राम के नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन गाय की सेवा नहीं करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राम मंदिर बन रहा है। हम गौमाता की सेवा कर रहे हैं। राम हमारा भांजा है। हमारे राम आदिवासियों के राम भी हैं। हमारे राम हैं, वो सबरी के राम हैं। हमारे राम कौशल्या के राम हैं। हम राम को साकार रूप में हो या निराकार रूप में हो, दोनों में मानने वालों में से हैं। राम सर्वव्यापी हैं, हम उनको पूजते हैं, उनके नाम से वोट नहीं मांगते हैं। वर्तमान केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है।

न्याय के चार साल : राज्य में आदिवासी कल्याण के आम फैसले

छत्तीसगढ़ ग्रामीण आदिवासी बहुल राज्य है. यहां की लोक संस्कृति हो या सुदूर वनांचल बस्तर-सरगुजा की जीवनशैली या फिर यहां की प्राकृतिक खूबसूरती बरबस ही सबके मन को मोह लेती है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने शानदार पारी के 48 माह पूरे कर लिए हैं. वैसे जानने वाले कहते हैं कि वे वादों के पक्के हैं, उनमें जुनून और जज्बा जबरदस्त है, जो कहते हैं, वे करते भी हैं. छत्तीसगढ़ के इतिहास में 17 दिसम्बर 2018 स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो चुका है. स्वर्ण अक्षरों में इसलिए क्योंकि राज्य बनने के बाइस बरस बाद पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग से आने वाले किसान पुत्र भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली.

मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण के तत्काल बाद उनके मंत्रिमण्डल सहित पूरे काफिले का रूख नया रायपुर स्थित प्रदेश के सबसे बड़े प्रशासनिक केन्द्र यानी महानदी भवन, मंत्रालय की ओर हुआ था और यहां से शुरू हुआ आदिवासी हितों के लिए गहन विचार-विमर्श का सिलसिला. यहां सबसे पहले बस्तर जिले के लोहणीगुड़ा के किसानों की इस्पात संयंत्र के लिए अधिगृहीत की गई जमीन वापस करने का निर्णय लिया गया. सरकार बनाने के महज दो माह के भीतर 16 फरवरी 2019 को 1707 किसानों की 4200 एकड़ जमीन के दस्तावेज उन्हें लौटा दिए गए. निर्णय और न्याय दो रास्ते को चुनते हुए भूपेश सरकार ने 12 लाख से अधिक तेन्दूपत्ता संग्राहकों को सौगात देते हुए तेन्दूपत्ता संग्रहण दर पच्चीस सौ रूपए से बढ़ाकर चार हजार रुपए प्रति मानक बोरा किया. चालू वर्ष 2022 के दौरान करीब 18 लाख मानक बोरा तेन्दूपत्ता का संग्रहण किया गया है जो लक्ष्य से 94 प्रतिशत से अधिक है. वहीं मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर समर्थन मूल्य परलघु वनोपजों की खरीदी की प्रजातियों को 7 से बढ़ाकर 65 किया जा चुका है. वनोपज संग्रहण में करीब 48 हजार



महिला स्व-सहायता समूह के सदस्य लाभान्वित हुए हैं. 134 उत्पादों का प्रसंस्करण कर छत्तीसगढ़ 'हर्बल ब्रांड' के नाम पर विक्रय शुरू किया गया है, साथ ही 30 संजीवनी केन्द्रों के माध्यम से करीब 200 उत्पादों का विपणन कार्य जारी है. वहीं लघु वनोपजों की संग्रहण दरों में भी वृद्धि की गई. शहीद महेंद्र कर्मा तेन्दूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 4692 तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवारों को 71.08 करोड़ से अधिक की बीमा दावा राशि का भुगतान किया गया है. 'इंदिरा वन मितान योजना' के तहत 85 आदिवासी विकासखण्डों में दस हजार युवा समूहों का गठन किया गया है, इससे 19 लाख परिवारों को लाभ हो रहा है. वन अधिकार अधिनियम के तहत निरस्त वन अधिकार पट्टों की समीक्षा कर अब तक साढ़े चार लाख 55 हजार से अधिक व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र करीब 46 हजार सामुदायिक वन अधिकार पत्र और लगभग चार हजार

सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं।

भूपेश सरकार ने आदिवासियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों की वापसी करने का एक अहम निर्णय लिया। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश ए.के पटनायक की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है। भूपेश सरकार ने निर्णय और न्याय के साथ आदिवासी युवाओं को रोजगार मुहैया कराने की दिशा में भी अनेक कदम उठाए हैं। बस्तर और सरगुजा संभाग के लिए शिक्षकों की भर्ती अभियान, इन्हीं दोनों संभागों के लिए जिलास्तरीय एवं संभागस्तरीय तृतीय एवं

है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने आम लोगों के बीच अस्पताल पहुंचाने के लिए 'मुख्यमंत्री हाट-बाजार क्लीनिक योजना' वर्ष 2019 में गांधी जयंती के दिन शुरू की थी।

सुदूर वनांचल, पहाड़, नदी, जंगल तथा दुर्गम गांवों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच आसान करना ही इस योजना का मुख्य ध्येय है। करीब 2 हजार हाट-बाजारों में अब तक एक लाख से अधिक शिविर आयोजित किए जा चुके हैं तथा 62 लाख से अधिक लोगों का इताज हुआ है। मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के तहत बस्तर संभाग में मलेरिया सकारात्मकता दर 4.60 प्रतिशत से घटकर

साधारण मेम्बरीन, पुजारियों सहित अन्य सदस्यों के मानदेय बढ़ाने की बात हो या फिर विश्व आदिवासी दिवस पर सार्वजनिक अवकाश भूपेश बघेल का हर कदम आदिवासियों के हित में है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहली बार राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव जैसे आयोजन कर श्री बघेल ने आदिवासी लोककला, लोककलनृत्य और लोक संस्कृति को केन्द्र में लाया है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने विगत चार वर्षों में 'गढ़बो नवा छत्तीसगढ़' की अवधारणा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित ही इन योजनाओं से आदिवासियों का जीवनस्तर ऊंचा उठा है और भूपेश सरकार के प्रति आम लोगों का विश्वास भी बढ़ा है।

एल.डी. मानिकपुरी,
(सहायक सूचना अधिकारी,
जनसम्पर्क)



चतुर्थ श्रेणी के पदों में स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने की पहल सराहनीय है। बस्तर संभाग के सभी जिलों में 'बस्तर फाइटर्स' विशेष बल के तहत स्थानीय युवाओं को नौकरी दी जा रही है। संवेदनशील मुख्यमंत्री की पहल पर ही धुर नक्सल प्रभावित सुकमा जिले के जगरण्डा में विगत 13 वर्षों से बंद 300 स्कूलों को फिर से शुरू किया गया। फिर से स्कूल खुलने से यहां बच्चों की खुशी और अभिभावकों का उत्साह देखने को मिल रहा।

0.21 पर पहुंच गया है। बीते चार वर्षों में छत्तीसगढ़ में मलेरिया के मामले में 65 फीसदी की कमी आई है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने सबको भरपेट भोजन मिले इसके लिए सार्वभौम पीडीएस योजना शुरू की है, जिसके तहत करीब 21 लाख अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को इसका लाभ हुआ है। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान हो या मधुर गुड योजना, देवगडियों का विकास हो या मांझियों, चालकियों, कार्यकारिणी व

न्याय के चार साल : छत्तीसगढ़ में और बढ़ेगा बिजली का उत्पादन

छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जिसे जीरो पॉवर कट के रूप में जाना जाता है। यहां उपभोक्ताओं को 24X7 बिजली आपूर्ति हो रही है। किसी भी प्रदेश की तरक्की का सबसे बड़ा सूचक वहां के ऊर्जा की खपत को माना जाता है। छत्तीसगढ़ में ऊर्जा की खपत तेजी से बढ़ रही है। राज्य स्थापना के समय जहां प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 300 यूनिट थी, वह आज बढ़कर 2044 यूनिट पहुंच चुकी है। भविष्य में ऊर्जा की मांग को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिये हैं।

रायपुर, छत्तीसगढ़ में ऊर्जा उत्पादन के इतिहास में एक मील का पथर और स्थापित हो गया जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 25 अगस्त को 1320 मेगावाट के नए पॉवर प्लांट लगाने का निर्णय लिया। वास्तव में यह छत्तीसगढ़ को बरसों बरस तक जीरो पॉवर कट स्टेट बनाए रखने की दिशा में ऐतिहासिक फैसला है। यह निर्णय इसलिये भी ऐतिहासिक है क्योंकि यह छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक संयंत्र होगा। इसकी स्थापना से छत्तीसगढ़ स्टेट जनरेशन कंपनी के स्वयं की विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़कर 4300 मेगावाट हो जाएगी।



मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद पॉवर जनरेशन कंपनी के कोरबा पश्चिम में 660-660 मेगावाट के दो सुपर क्रिटिकल नवीन विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाने की कार्ययोजना बनाने पर कार्य प्रारंभ हो गया है। इस संयंत्र के निर्माण में 12915 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है। इन दोनों इकाइयों को वित्तीय वर्ष 2029 और 2030 में पूर्ण करने का लक्ष्य है। राज्य स्थापना के बाद पहली बार इतनी क्षमता का विद्युत संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। यह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की दूरदर्शिता को दर्शाता है।

छत्तीसगढ़ की धरती में अकूत खनिज संसाधन हैं। कोयले के भंडार मामले में छत्तीसगढ़ देश में तीसरे नंबर पर है। इन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग देशभर के पॉवर प्लांट में हो रहा है। परन्तु इसका लाभ इस धरती के निवासियों को नहीं मिल पाता है। अगर यहां के खनिज संसाधनों से उद्योग यहां स्थापित होते हैं तो यहां के लोगों को इसका सीधा लाभ मिलता है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की केबिनेट ने बिजली उत्पादन के क्षेत्र में दूसरा बड़ा फैसला पानी से बिजली बनाने के क्षेत्र में लिया है। केबिनेट में छत्तीसगढ़ राज्य जल विद्युत परियोजना (पंप स्टोरेज आधारित) स्थापना नीति 2022 को मंजूरी दी गई है। वर्तमान में जो जल विद्युत संयंत्र हैं, उनमें बांध में बारिश के पानी को एकत्रित किया जाता है और उसे टरबाइन में बहाकर बिजली पैदा की जाती है। इस पुराने तकनीक में पानी का इस्तेमाल केवल एकबार ही किया जाता है। वर्तमान में नई पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजना तैयार की गई है, जिसमें एक ही पानी का इस्तेमाल कई बार किया जा सकेगा। इस तकनीक में बांध के ऊपर एक और स्टोरेज टैंक बनाया जाता है। दिन के समय सौर ऊर्जा से मिली सस्ती बिजली से इस टैंक में पानी स्टोरेज किया जाएगा और रात में उसे टरबाइन में गिराकर बिजली पैदा की जाएगी। यह पानी फिर से बांध में एकत्रित कर लिया जाएगा। इस तरह एक ही पानी का बार-बार इस्तेमाल किया जा सकेगा।



छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी ने प्रदेश में ऐसे पांच स्थानों पर पंप स्टोरेज जल विद्युत गृह की स्थापना के लिए विस्तृत कार्ययोजना बना रही है। इन पांच स्थानों पर 7700 मेगावाट बिजली पैदा हो सकेगी। डीपीआर बनाने के लिए केंद्र सरकार की एजेंसी वैपकास (वाटर एंड पॉवर कंसल्टेंसी सर्विसेस लिमिटेड) के साथ 29 नवंबर को एमओयू किया गया है। राज्य में पम्प स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 6 सितम्बर को आयोजित केबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य जल विद्युत परियोजना (पंप स्टोरेज आधारित) स्थापना नीति 2022 का अनुमोदन किया गया।

इन दोनों फैसलों से यहां के निवासियों के लिये रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। संयंत्र की स्थापना से लेकर उसके संचालन के लिये जहाँ हजारों लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा। इस संयंत्र की स्थापना अत्याधुनिक तकनीक से की जाएगी, जिसमें बहुत कम प्रदूषण होगा। इससे भविष्य में ऊर्जा की बढ़ती मांग पूरी हो सकेगी। इस फैसले से प्रदेश में उद्योग से लेकर कृषि क्षेत्र में प्रगति के नए पंख लगेंगे और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को तीव्र गति मिलेगी। यह फैसला आने वाले बरसों में छत्तीसगढ़ के लिये मील का पत्थर होगा।

आलेख-गोविंद पटेल, प्रबंधक
(जनसम्पर्क)



भूपेश सरकार के राज में बदला सुकमा गर्भवती के लिए बनाया ग्रीन कॉरिडोर

रायपुर. भूपेश सरकार के चार साल पूरे हो गए हैं और अब प्रदेश भी बदल चुका है, सुकमा जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में एक गर्भवती के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया।

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र सुकमा में एक महिला की डिलीवरी होनी थी, दर्द शुरू हो गया था, लेकिन परिवार के सामने बड़ी चुनौती महिला को सुरक्षित तरीके से अस्पताल पहुंचाने की थी। ऐसे वक्त पर देवदूत बनकर आए कोबरा और सीएपीएफ के जवानों ने आनन फानन में ग्रीन कारीडोर बना दिया और महिला को सुरक्षित तरीके से अस्पताल पहुंचाया। सुरक्षा बलों की इस मानवीय कार्य की अस्पताल के डॉक्टरों पर महिला के परिजनों ने खूब तारीफ की है। कहा कि यदि समय पर मदद नहीं मिलती तो महिला की जान भी जा सकती थी।



जानकारी के मुताबिक सुकमा के अति संवेदनशील इलाके में रहने वाली महिला थोड़ी मात्रा गर्भवती थी। रविवार की शाम को अचानक से उसके पेट में दर्द शुरू हो गया। स्थिति क्रिटिकल थी। स्थानीय उपाय काम नहीं आए और अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़ गई। लेकिन परिवार को नक्सलियों से खतरा था। ऐसे वक्त पर परिवार के ही किसी व्यक्ति ने सुरक्षा बलों को सूचना दी। इसके बाद सुरक्षा बल के जवानों ने आनन फानन में महिला के घर से लेकर अस्पताल तक ग्रीन कारीडोर बना दिया। इसके बाद अपनी गाड़ी में लिटाकर महिला को अस्पताल पहुंचाया। यहां महिला ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है।

थोड़ी देर होती तो खतरे में आ जाती महिला की जान

डॉक्टरों ने बताया कि महिला की स्थिति क्रिटिकल थी। यदि उसे अस्पताल पहुंचने में थोड़ी और देर होती तो उसे और उसके बच्चे को बचाना मुश्किल हो जाता। डॉक्टरों ने सुरक्षा बलों को धन्यवाद दिया है। कहा कि सुरक्षा बलों की सक्रियता और मानवीयता के चलते ही महिला की जान बचाई जा सकी है। सुरक्षा बलों के चलते ही यह महिला ना केवल सुरक्षित तरीके से अस्पताल पहुंची है, बल्कि समय रहते उसका इलाज भी शुरू हो सका है।

बेहद खतरनाक इलाका है सुकमा

छत्तीसगढ़ का सुकमा नक्सल प्रभावित इलाका होने की वजह से बेहद खतरनाक है। यहां नक्सली आएँदिन हमले करते रहते हैं। पिछले दिनों ही यहां नक्सलियों ने सुरक्षाबलों पर बम से हमला किया था। इसके अलावा आएँदिन वह नागरिकों को भी शिकार बनाते हैं। ऐसे में यहां के लोग 24 घंटे डर के साथ जीने को मजबूर हैं।

जहां टेल नहीं, वहां भी घर तक पहुंचेगा पार्सल

रायपुर: लोगों को अपना सामान ट्रेन में बुक करने या लेने के लिए रेलवे स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है. रेलवे अब लोगों के घर तक उसका पार्सल पहुंचाएगा. बुक हो या बाइक, सबकुछ लोगों के घर में डिलिवर होगा. यह सुविधा उन क्षेत्रों में भी मिलेगी, जहां ट्रेन नहीं चलती. एसईसीआर इस योजना के लिए पोस्ट ऑफिस से हाथ मिलाने वाला है. पार्सल क्षेत्र में कई कंपनियां करोड़ों रुपए की कमाई कर रही हैं. इस क्षेत्र में मोटी कमाई करने के लिए रेलवे भी मौदान में उतरने वाला है. डाकघर के साथ पूरी योजना लगभग तैयार कर ली गई है. डाक विभाग के जरिए आपके घर तक पार्सल की डिलवरी होगी. बिलासपुर मंडल के उन क्षेत्रों में जहां ट्रेन चलना तो दूर पटरी तक नहीं है, वहां के लोगों को भी यह सुविधा मिलेगी. अभी तक पार्सल बुक करने और लेने के लिए लोगों को रेलवे स्टेशन तक जाना पड़ता था. दूसरी तरफ, जहां ट्रेनों को परिचालन ही नहीं होता है, वहां के लोग ट्रेन में पार्सल बुक ही नहीं करते थे. एसईसीआर की यह योजना शुरू होते ही इन क्षेत्र के लोगों को काफी राहत मिलेगी.

पार्सल पहुंचने के 24 घंटे के अंदर डाक विभाग को इसकी डिलवरी करनी होगी. बुक से लेकर बाइक तक लोगों को घर में मिलेगी. बिलासपुर मंडल में एक माह के अंदर यह सुविधा शुरू हो सकती है. रेलवे के अधिकारी इस पर तेजी से कार्य कर रहे हैं. अगर कोई पार्सल आ रहा है, तो बार-बार इसकी जानकारी लेनी पड़ती थी.



प्रतिकिलो के हिसाब ले लिया जाएगा

शुल्क

रेलवे द्वारा पार्सल के लिए प्रति किलो के हिसाब से शुल्क लिया जाएगा. पार्सल 35 से 100 किलो के बीच होना चाहिए. इसके लिए 12 से 15 रुपए प्रति किलो शुल्क निर्धारित किया जा सकता है. लोग अपना समान कहीं भी ट्रेन से भेज सकते हैं.

पार्सल आते ही डाक विभाग लेगा कब्जे में

ट्रेन से पार्सल आने पर सीधे गोदाम में उतरेगा. इस पार्सल को डाक विभाग तत्काल अपने कब्जे में लेगा. वहीं पार्सल के पते पर इसे 24 घंटे के अंदर पहुंचाएगा. रेलवे का कार्य सिर्फ पार्सल को लाना-लेजाना रहेगा. वहीं डिलवरी का पूरा कार्य डाक विभाग का होगा.



जयपुर. दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड की तरह ही जयपुर में भी सनसनीखेज मामला सामने आया है. एक 33 वर्षीय इंजीनियर भटीजे को धार्मिक कार्यक्रम में दिल्ली जाने से ताई का रोकना इतना नागवार गुजरा कि उसने हथौड़ा मार कर मृतका सरोज ताई की हत्या कर दी. इसके बाद मार्बल कटर से शव के दस टुकड़े कर ट्रॉली बैग में भर दिल्ली रोड पर 4 जगह फेंककर मिट्टी डाल दी. हत्या के 6 दिन बाद पुलिस ने मामले का खुलासा कर - तीन जगह से शव के आठ टुकड़े बरामद कर लिए. शेष दो टुकड़ों की तलाश कर रही है. मृतका की बेटी की रिपोर्ट पर आरोपी अनुज शर्मा उर्फ अचिंत्य गोविंद दास को गिरफ्तार कर लिया है. वारदात विद्याधर नगर के सेक्टर-2 स्थित लालपुरिया -अपार्टमेंट में 11 दिसंबर को हुई. ताई सरोज देवी (65) ने भटीजे अनुज शर्मा को एक धार्मिक कार्यक्रम में दिल्ली जाने से रोका तो वह गुस्सा हो गया. अपनी ताई के सिर पर हथौड़े से चार- पांच बार किए, जिससे सरोज की मौत हो गई. अनुज शव को बाथरूम में ले गया. शव को चाकू से काटने की कोशिश की, फिर बाजार से 1500 में मार्बल -कटर ले आया. शव के 10 टुकड़े कर ट्रॉली बैग में भरकर कार से दिल्ली जाने से ताई ने रोका तो ले ली जान.

ऐसे चला घटनाक्रम

11 दिसंबर, सुबह 10:30 बजे हथौड़े से हत्या की. मार्बल कटर से शव के 10 टुकड़े किए. सायं 4 बजे शव के टुकड़े बैग में रखकर घर से निकला. रात 8 बजे दिल्ली रोड पर शव के टुकड़ों को फेंककर लौटा. रात 9 बजे जाकर गुमशुदगी दर्ज कराई खुद थाने में दर्ज कराई.

12 दिसंबर मृतका की बेटी को फोन पर ताई की गुमशुदगी की सूचना दी. जयपुर पहुंचने पर घर में मृतका की बेटी को खून के धब्बे दिखने पर हुआ शक.

13 दिसंबर आरोपी अनुज हरिद्वार चला गया.

इंजीनियर ने ताई की हथौड़े से की हत्या, शव के 10 टुकड़े कर जंगल में फेंके



15 दिसंबर परिजन ने आरोपी को दिल्ली बुलाया.

16 दिसंबर परिजन दिल्ली से आरोपी को जयपुर लाए. रात को पुलिस ने शव के आठ टुकड़े बरामद किए.

बहन और पिता गए हुए थे इंदौर....

आरोपी अनुज ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रखी है. एक साल प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने के बाद दीक्षा लेकर एक धार्मिक संस्था से जुड़ गया. वह दिल्ली व हरिद्वार के कार्यक्रमों में आता जाता रहता था. घर में अनुज और उसके पिता (बैंक के एजीएम पद से रिटायर) बड़ी प्रसाद (65), अनुज की बड़ी बहन और ताई सरोज थे. आरोपी की माँ की कोरोना काल में मौत हो गई थी. एडीसीपी धर्मेंद्र सागर ने बताया कि आरोपी के पिता व बहन 11 दिसंबर को इंदौर गए हुए थे. इंदौर में बहन के रिश्ते की बात चल रही है.

कैंसर से पीड़ित थी नृतका सरोज

सरोज शर्मा अजमेर की रहने वाली थी. कैंसर से पीड़ित होने के कारण वह इलाज के लिए जयपुर आकर यहां रहने लगी. उसकी दो बेटियां मोनिका और पूजा हैं. उसका बेटा अमित शर्मा कनाडा में परिवार के साथ रह रहा है. पति का वर्ष 1995 में निधन हो गया था.

मृतका की बेटी ने देखा खून, बुलाया पुलिस को

वारदात के दौरान रसोई व बाथरूम में कई जगह खून के धब्बे रह गए थे. आरोपी समय-समय पर उन्हें साफ करता रहा. इस दौरान 12 दिसंबर को मृतका की बेटी मोनिका ने उसे रसोई से खून के धब्बे हटाते देख लिया. मोनिका ने पूछा तो बोला मुझे नक्सीर आ गई थी. मोनिका ने यह बात गुमशुदगी की जांच कर रहे कांस्टेबल देवीलाल को बताई. उसने पौके पर पहुंच कर सीसीटीवी फुटेज खंगाले.

आरोपी निकल गया हरिद्वार...

अनुज कुछ काम होने की बात कहकर हरिद्वार के लिए निकल गया. वह हरिद्वार से दिल्ली पहुंच गया. इसकी सूचना कांस्टेबल देवीलाल ने एसएचओ वीरेंद्र कुरील को दी. पुलिस ने परिजन के जरिए बुलाने का प्रयास किया तो आया नहीं. उसके बाद परिजन खुद कार लेकर दिल्ली गए और अनुज को साथ लेकर आए. जयपुर पहुंचते ही पुलिस उसे थाने ले आई. पूछताछ में आरोपी ने हत्या की बात कबूल कर ली.

डायनासोर का सिर 50 करोड़ रुपये में नीलाम



स्टेन नामक टी-रेक्स ने बनाया था नया रिकार्ड

स्यू का रिकार्ड स्टेन नामक टी-रेक्स ने तोड़ा था। टी-रेक्स 2020 में 3.18 करोड़ डॉलर में बिका था। वहीं, इसी साल शेन नाम का एक टी-रेक्स 2.5 करोड़ डॉलर में नीलाम किया गया। वहीं, 2022 में एक गोर्गोसॉरस नामक जीवाशम 61 लाख डॉलर में नीलाम हुआ था।

इन जीवाशमों को खरीदते हैं कलाप्रेनी

लंदन के नेचुरल हिस्टोरियन संग्रहालय के वरिष्ठ डायनासोर विशेषज्ञ, प्रोफेसर पॉल बैरेट ने कहा, इन्हें खरीदने वाले विशेषज्ञ संग्राहक होते हैं। उन्होंने बताया, नीलामी के जरिए डायनासोर के जीवाशमों को खरीदने वाले आमतौर पर कला में अधिक रुचि रखते हैं। उन्हें डायनासोर की दुर्लभता और सौंदर्य का मूल्य पता होता है। एक तरह से वह उनके व्यक्तित्व की परछाई को दिखाता है।

वाशिंगटन। 'न्यूयार्क लक्जरी वीक' में एक डायनासोर के सिर को 50.22 करोड़ रुपये में नीलाम किया गया है। इस डायनासोर का नाम 'मैकियमस' है। यह डायनासोर की सबसे पुरानी प्रजातियों में से एक टायरानोसॉरस रेक्स का सिर है। इसे सबसे महंगे बिकने वाले जीवाशमों में से एक माना जा रहा है। 'मैकियमस' नाम का यह डायनासोर 20 दुर्लभ प्रजातियों के जीवाशमों में से एक है। 'स्यू' नाम के जीवाशम की सबसे पहले हुई थी नीलामी बता दें कि जीवाशमों की नीलामी की शुरुआत 1997 में हुई थी। सबसे पहले 'स्यू' नाम के एक टी-रेक्स जीवाशम को अमेरिका में 84 लाख डॉलर में नीलाम किया गया था। यह वह दोर था जब जुरासिक पार्क फिल्म का सीक्वल द लॉस्ट वर्ल्ड रिलीज हुई थी और डायनासोर के कंकालों में लोगों रुचि बढ़ने लगी थी।



नई दिल्ली, भारत की सरगम कौशल को शनिवार को मिसेज वर्ल्ड 2022 चुना गया, वह 63 देशों की प्रतियोगियों को मात देकर विजेता बनी हैं। 21 साल बाद किसी भारतीय महिला ने यह खिताब अपने नाम किया, लास वेगास के वेस्टगेट रिजार्ट एंड कसीनो में आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व विजेता अमेरिका की शायलिन फोर्ड ने उन्हें ताज पहनाया।

इस दौरान मिसेज पोलिनेशिया प्रथम उपविजेता और मिसेज कनाडा दूसरी उपविजेता बनीं, मिसेज इंडिया पेंजेंट ने रविवार को अपने इंस्टाग्राम पेज पर यह जानकारी साझा की है, पोस्ट में कहा गया कि लंबा इंतजार खत्म हो गया है, 21 साल बाद हमारे पास खिताब वापस आ गया है।

क्या है मिसेज वर्ल्ड स्पर्धा

मिसेज वर्ल्ड दुनिया का पहला ऐसा व्यूटी पेंजेंट है, जिसे शादीशुदा महिलाओं के लिए आयोजित किया जाता है। इसकी शुरुआत साल 1984 में हुई थी, पहले इसका नाम 'मिसेज अमेरिका' था, जिसे बाद में 'मिसेज वुमन ऑफ द वर्ल्ड' कर दिया गया था। साल 1988 में इसका नाम 'मिसेज वर्ल्ड' पड़ा, पहला मिसेज वर्ल्ड खिताब जीतने वाली महिला श्रीलंका की रोजी सेनायायाके थीं।

'मैं बहुत उत्साहित हूं, लव यू इंडिया'

वहीं, कार्यक्रम के दौरान सरगम कौशल ने कहा, 21 साल बाद हमारे देश को ताज वापस मिल गया है, मैं बहुत उत्साहित हूं, लव यू इंडिया, लव यू वर्ल्ड। उनसे पहले साल 2001 में मॉडल अदिति गोविंत्रिकर ने यह खिताब अपने नाम किया था।

21 साल बाद भारत की सरगम बनी मिसेज वर्ल्ड



भावना का डिजाइन किया हुआ गड़न पहना

पूर्व मिसेज वर्ल्ड अदिति गोविंत्रिकर ने भी इंस्टाग्राम में एक बधाई संदेश साझा किया है, इसमें उन्होंने सरगम कौशल को टैग करते हुए लिखा कि बहुत खुश हूं, सफर का हिस्सा बनने के लिए हार्दिक बधाई कौशल, ताज 21 साल बाद फिर वापस आ गया है, बता दें कि सरगम को प्रतियोगिता के लिए मॉडल एलेसिया राउत ने ट्रेनिंग दी थी, सरगम ने फाइनल राउंड के लिए भावना राव द्वारा डिजाइन किया गया एक गुलाबी रंग का गाउड़न पहना था।

कौन हैं सरगम कौशल

32 साल की सरगम कौशल जम्मू-कश्मीर की रहने वाली है, उन्होंने इंग्लिश लिट्रेचर में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, सरगम विशाखापट्टनम में बतौर अध्यापिका भी काम कर चुकी है, सरगम की शादी 2018 में हुई थी, वर्तमान में सरगम कौशल के पति भारतीय नौसेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।



कैंसर मरीजों की बेचैनी कम करेगा संगीत

◆ नई दिल्ली। दुनियाभर में करोड़ों लोग कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। अब शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन में बताया कि संगीत सुनने से कैंसर रोगियों के दर्द और तनाव को कम किया जा सकता है। यह शोध यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स कॉर्नर हॉल हेल्थ ने हाल ही में किया, जिसमें कैंसर रोगियों को म्यूजिक थेरेपी दी गई। ◆

शोध में निष्कर्ष निकला कि म्यूजिक थेरेपी से कैंसर के मरीजों की बेचैनी और तनाव कम होता है। हाल ही में जर्नल इंटीग्रेटिव कैंसर थेरेपीज में प्रकाशित एक नए शोध के अनुसार, यूएच कॉर्नर हॉल हेल्थ के म्यूजिक थेरेपिस्ट ने 1,152 कैंसर मरीजों को 4,002 म्यूजिक थेरेपी सेशन दिए। जिसमें पाया गया कि संगीत थेरेपी प्रोग्रामिंग रोगियों और परिवार के सदस्यों के लिए उनकी कैंसर यात्रा के दौरान लक्षण प्रबंधन का एक अनूठा और प्रभावी तरीका है। 'क्लिनिकल डिलीवरी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ म्यूजिक थेरेपी इन हेमेटोलॉजी एंड ऑन्कोलॉजी' में शोधकर्ताओं ने यूएच सीडमैन कैंसर सेंटर में क्लिनिकल डिलीवरी और म्यूजिक थेरेपी की प्रभावशीलता की जांच की और दर्द, चिंता और थकान के बीच संगीत थेरेपी की प्रभावशीलता की तुलना की।

शोध के निष्कर्ष में बताया गया कि जिन वयस्क रोगियों ने म्यूजिक थेरेपी ली उनमें बीमारी से मुकाबला, दर्द प्रबंधन, चिंता में कमी, और आत्म अभिव्यक्ति देखा गया।



इलाज के लिए 'म्यूजिक थेरेपी' का हो रहा इस्तेमाल

संगीत चिकित्सा या म्यूजिक थेरेपी में किसी मरीज को संगीत का अनुभव कराया जाता है। इसमें संगीत सुनना, गाना गाना, गाने लिखना, संगीत की चर्चा करना आदि चीजें शामिल होती हैं। माना जाता है कि म्यूजिक थेरेपी से इंसान के शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है और यह उन्हें किसी भी चीज से लड़ने की ताकत देती है। संगीत का इस्तेमाल अब इलाज में भी किया जा रहा है।



एनडीटीवी : मसला सिर्फ एक चैनल या पत्रकार का नहीं है



एनडीटीवी के जबरिया और तिकड़मी टेकओवर पर देश भर में विक्षोभ और चिंता की लहर सी उठी है। मीडिया के भविष्य को लेकर फिक्र बढ़ी है - ज्यादातर लोगों ने इसे ठीक उसी तरह लिया है, जिस तरह लिया जाना चाहिए और वह यह कि : एनडीटीवी का अधिग्रहण उसे चलाने के लिए नहीं, उसे उसके मौजूदा स्वरूप में न चलने देने के लिए किया गया है। यह अधिग्रहण भारत के इतिहास में अब तक की सबसे देशधाती और निरंकुश हुकूमत को चलाने वाले गंठजोड़ के अपकर्मों को उजागर करने वाली हर छोटी - बड़ी संभावना को समाप्त करने के लिए है। सूचना के हरेक छोटे-बड़े स्रोत को गोद में बिठाकर उसे मालिक की अपनी आवाज - हिज मार्टर्स वॉइस - में बदल देने के लिए है।

ठीक यही बजह है कि इस अधिग्रहण को सिर्फ रवीश कुमार या एनडीटीवी तक सीमित रखकर देखना समस्यापूर्ण नजरिया है। निस्संदेह रवीश कुमार हमारे समय के बड़े पत्रकार हैं, एक बेहद कठिन समय में उन्होंने पत्रकारिता की लाज ही नहीं रखी, उसे एक नयी वर्तनी, मुहावरा और जन, खासकर हिंदी भाषी दर्शकों के बीच सम्मान प्रदान किया है। उन्होंने आम आदमी को - लोक को - खबरों का केंद्र बनाया है, पत्रकारों की एक पूरी पीढ़ी को प्रभावित किया है और इसी के साथ युवा पत्रकारों की एक पूरी टीम - जिसमें इसी वर्ष के लोकजनन सम्मान से अभिनंदित अनुराग द्वारी भी है - तैयार की है और ऐसा करते हुए जनता के बीच भी असाधारण लोकप्रियता हासिल की है।

इसमें भी कोई शक नहीं कि प्रणव और राधिका राय ने एनडीटीवी को व्यावसायिक संस्थान के रूप में चलाते हुए भी भारत के मीडिया - विजुअल मीडिया - का एक अलग तरह का मानक बनाया है। सनसनी और प्रायोजित तड़के में बघरे प्रोपेंडंग की जगह खबरों को अपेक्षाकृत सलीके से पेश करने की सलाहियत दी है। तात्कालिक राजनीतिक दबावों में न आकर अक्सर अपनी रीढ़ की सलामती का सबूत दिया है। तय है, ऐसी हालत में कुछ घाटे उठाने पड़ते हैं और यह जबरिया अधिग्रहण ऐसे ही घाटों में से एक है, मगर फिर भी इस पूरे घटनाविकास को सिर्फ रवीश कुमार या एनडीटीवी तक पर केंद्रित कर देखने से इस घटना के वास्तविक निहितार्थ को नहीं समझा जा सकता। ऐसा करते में उन खतरों को भी अनदेखा कर दिए जाने की आशंका है, जो इस अधिग्रहण से सामने आये हैं।

एनडीटीवी का अडानी टीवी बन जाना हमारे कालखण्ड की एक ऐसी दुर्घटना है, जिसका प्रभाव आने वाले दिनों में समूचे मीडिया पर धनपशुओं और उनकी पालित-पोषित सत्ता के वर्चस्व की संपूर्णता के रूप में दिखेगा। इसलिए इसे व्यक्तियों से ऊपर उठकर प्रवृत्तियों के हिसाब से देखना उचित होगा। इस अधिग्रहण के बाद लंदन में बोलते हुए गौतम अडानी ने दावा किया है कि अब तक भारत में कोई भी ऐसा चौनल नहीं है, जो विश्व स्तर का हो, इसलिए वे एनडीटीवी को नया रूप देकर उसे एक विश्व स्तर का चौनल बनाना चाहते हैं। वे भूल गए कि ऐसा कहते में वे एक तरह से खुद अपने स्वामित्व वाले मीडिया सहित भारत के बाकी चौनलों को स्तरहीन बताते हुए उन्हें आईना दिखा रहे थे। उसके क्षण के 2014 के बाद पूर्ण पराभव का शिकार होकर गोदी मीडिया में बदल जाने की स्थिति को स्वीकार कर रहे थे। मगर स्वीकारोक्ति का यह पूर्ण सच भी असल में आंशिक सच ही है। जैसा कि ऊपर लिखा गया है रू एनडीटीवी का अधिग्रहण उसे चलाने के लिए नहीं, उसे उसके मौजूदा स्वरूप में न चलने देने के लिए किया गया है।

दूसरी बात यह कि जैसा कि कुछ विद्वानों द्वारा दावा किया जा रहा है यह वैसा, एक कंपनी का दूसरी में मिल जाना या किसी के द्वारा उसे खरीद लिया जाना जैसा कारोबारी कारनामा नहीं है। यह सिर्फ व्यावसायिक मामला नहीं है। यह मिल्कियत और स्वामित्व का एक धन्ना सेठ के हाथ से निकल कर दूसरे के हाथ में जाना भर नहीं है। हालाँकि किसी लोकतांत्रिक समाज में सवाल तो यही होना चाहिए था कि मीडिया किसी औद्योगिक घराने या धनासेठ के हाथ में होने ही क्यों चाहिये? बहरहाल यह "अखबार और अब आज का मीडिया टीवी वगैरह तो हमेशा ही किसी न किसी की पूंजीपति के हाथ में रहे हैं, इसलिए इसमें नया क्या है" जैसा अति सरलीकरण भी नहीं है। अडानी सामान्य धनासेठ नहीं है - उनकी उत्पत्ति और विकास पूंजीवाद के सामान्य नियमों पैसा जुटाना, उसके निवेश से संसाधन जुटाकर उत्पादन में लगाना, माल पैदा करना, उसे बेचकर मुनाफे के जरिये और पैसा कमाना जैसी प्रक्रिया के अनुसार नहीं हुई है। सत्ता से सांठगांठ करके की गयी तिकड़मों से राष्ट्र और जनता की सम्पत्तियाँ हड्डपने, बैंकों को लूटने के जरिये हुयी हैं। अर्थशास्त्र की भाषा में इसे आदिम संचय कहते हैं और पूंजीवाद की इस किस्म को दरबारी पूंजीवाद - क्रोनी कैपिटलिज्म - कहते हैं। इस दरबारी पूंजीपति का एनडीटीवी पर कब्जा करना पत्रकारिता को नयी ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए नहीं है। यह दरबार के लिए, दरबार द्वारा, दरबार का कारनामा है, जिसका मुख्य मकसद सिर्फ और केवल राजा का बाजा बजे, यह पक्का करना है।



यह बात अधिग्रहण की पूरी साजिश में बरती गयी रहस्यमयी गोपनीयता और सभी प्रचलित नियम, कानूनों को ताक पर रख इसे अंजाम देने में "ऊपर वाले" की भूमिका से भी साफ हो जाता है। एनडीटीवी द्वारा लिए गए 400 करोड़ रुपये का ऋण कर्जदाता कम्पनी से होते हुए अम्बानी के खाते में ट्रांसफर हो जाना और अम्बानी द्वारा उसे 300 करोड़ का घाटा उठाकर अडानी को सौंप देना व्यावसायिक गतिविधि नहीं है। यह घाटे का सौदा - बैड इकोनॉमिक्स - है और रिलायंस समूह इतना नादान और भोला नहीं है कि वह ऐसे नुकसानदायी सौदे करे, खासकर से तब जब अम्बानी खुद मीडिया के धंधे में हैं, इसके बहुत बड़े वाले कब्जाधारी हैं। अगर वे चाहते, तो जो 29.18 प्रतिशत शेयर्स उनके पास थे, उनके आधार पर एनडीटीवी का सम्पादकीय और प्रबंधकीय नियंत्रण हथिया सकते थे - मगर उन्होंने यह काम अडानी को सौंप दिया। जो मुकेश भाई अम्बानी इतनी उदारता अपने इकलौते सोगे भाई अनिल अम्बानी के साथ भी नहीं दिखाए थे, उन्होंने यह सद्भावनावश तो नहीं ही किया होगा। इसमें जरूर 'ऊपर वाले' का हाथ रहा होगा। इसलिए यह काण्ड सिर्फ व्यावसायिक चतुराई नहीं है, यह राजनीतिक घपला है। एक ऐसा घपला जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय की लिप्तता है - उन्होंने स्वयं अपने और अपने चहेते दरबारी पूँजीपति के हितसाधन के लिए सारी डोरों को हिलाया डुलाया है।

स्वतंत्र भारत में पूँजी के वर्चस्व और एकाधिकार - मोनोपोली - को रोकने के लिए एमआरटीपी एक्ट जैसे कानून रहे। मीडिया के बारे में खासकर से नीति रही कि इसमें विदेशी पूँजी न आये और देशी पूँजी भी अपनी थैलियों की दम पर अखबार, टीवी, रेडियो सहित चौतरफा एकाधिकार न जमाये। उदारीकरण की फिसलन शुरू होने तक आमतौर से इसका पालन हुआ। मगर 2014 में अधिवक्ति की स्वतंत्रता और अपने अपराधों के उजागर होने के डर से घबराने वालों के सत्तासीन होने के बाद से टाट उलट गया। आज भारत के जितने भी बड़े और ज्यादा प्रसार वाले अखबार, टीवी

चैनल्स आदि मीडिया समूह हैं, वे अम्बानी या अडानी के बटुये में समा चुके हैं। तीन साल पहले तक अम्बानी के रिलायंस के स्वामित्व में 80 करोड़ दर्शकों तक पहुँच वाले 72 टीवी चैनल्स थे। अडानी के हाथ में भी कोई आधा सैकड़ां चैनल्स की मालिकी थी। इस बीच यह संख्या और बढ़ी होगी। देश में सबसे ज्यादा प्रसार संख्या वाले खासकर हिंदी भाषा के - अखबारों को सीधे या आड़े-टेढ़े तरीकों से इन दोनों समूहों द्वारा कब्जाया जा चुका है। यह अभी आगाज है। अति केन्द्रीकरण पूँजीवाद का नियम और दूसरे देशों के अनुभव चिंताजनक तस्वीर दिखाते हैं। वर्ष 2011 में अमरीका में कोई 50-60 कम्पनियां थीं, जिन्होंने मीडिया के 90 प्रतिशत हिस्से पर कब्जा किया हुआ था। दस साल के भीतर ही आज स्थिति यह है कि 90 प्रतिशत अमरीकी मीडिया का कब्जा कुल जमा 5-6 कंपनियों के चंगुल में पहुँच गया। कहने की जरूरत नहीं कि इसके और अमरीकी राजनीति के ट्रंपीकरण के बीच सीधा संबंध है।

भारत में अब तक दो प्रेस कमीशन बने हैं, पहला 1954 में और दूसरा 1980-81 में ये इन दोनों ही प्रेस कमीशन का मानना था कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को बुनियादी खतरा मीडिया के औद्योगिक घरानों के स्वामित्व से है। इससे बचने के लिए उसने अनेक उपायों पर भी राय मशविरा किया था। मीडिया वर्चस्व निरुत्साहित करने के कदमों के अलावा उसने पूँजी घरानों पर मीडिया की अति-निर्भरता रोकने के लिए विज्ञापन नीति सुझाई थी, सरकारी विज्ञापनों के बारे में इस तरह के प्रावधान किये थे कि वे प्रकाशित सामग्री - कंटेंट - के आधार पर नहीं, प्रसार संख्या - सर्कुलेशन - के आधार पर मिले। मीडिया पर एकाधिकार रोकने के लिए क्षेत्रीय तथा स्थानीय अखबारों को इस विज्ञापन नीति में संरक्षण प्रदान किया गया था। सार्वजनिक नियंत्रण वाले प्रसारण संस्थान बने, उनकी पारदर्शिता और निष्पक्षता की देखेख के लिए प्रसार भारती और प्रेस कौसिल जैसे स्वतंत्र निकाय गठित हुए।

हालांकि इस समझदारी को ईमानदारी से कभी लागू नहीं किया गया। मोदी की अगुआई में कारपोरेट और हिंदुत्ववादी साम्प्रदायिकता के गठजोड़ के सत्ता में आने के बाद तो इस स्थिति को पूरी तरह उलट ही दिया गया। सरकारी और सार्वजनिक उद्यमों, संस्थानों के विज्ञापन दण्डवत करने के औजार बना दिए गए। मोदी राज में तो कारपोरेट और धन्नासेठों के विज्ञापन भी इसी आधार पर दिए और रोके जाने लगे। इसका जो असर होना था, वह हुआ भी ये मीडिया का रूप स्वरूप ही बदल गया, सम्पादक नाम की संस्था ही समाप्त हो गयी, पत्रकारों का गुणधर्म ही बदल दिया गया। नतीजा सामने है: दुनिया के पत्रकारों के प्रतिष्ठित संगठन 'रिपोर्टर्स विथाउट बॉर्डस' की रिपोर्ट के अनुसार भारत प्रेस स्वतंत्रता के मामले में 180 देशों में 150वें नंबर पर है - 2021 में यह नंबर 142 था - यह गिरावट लगातार जारी है। यह बढ़ती हुयी तानाशाही का एक प्रमुख संकेतक है।

ठीक यही वजह है कि यह मसला सिर्फ एक पत्रकार या एक टीवी चैनल का नहीं है। इसलिए इसका जवाब यूट्यूब चैनल शुरू करके या टिवटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स बढ़ाकर नहीं दिया जा सकता। सोशल मीडिया कहे जाने वाले ये सभी माध्यम भी अब 'बग ब्रदर' की निगाहों में हैं। अल्पोरिथम का प्रबंधन और इस्तेमाल करके उन पर भी अंकुश लगाया जाने लगा है। यह तानाशाही सिर्फ मीडिया का गला घोंटने तक सीमित नहीं रहने के लिए नहीं आयी है - यह पूँजीवादी लूट का निर्ममतम राजनीतिक रूप है, इसलिए इसका मुकाबला भी राजनीतिक धरातल पर ही हो सकता है।

(आलेख : बादल सरोज)

मोदी सरकार के मंत्री ने की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तारीफ

रायपुर. पर्यावरण की सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की दूरदर्शी सोच से शुरू हुई गोधन व्याय योजना का पूरा देश मुरीद हो चुका है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस योजना की शुरुआत की थी जो आज पूरी तरह से सफल होती नजर आ रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी शासकीय विभागों के लिए निर्देश जारी किया है कि अब शासकीय कार्यालयों, निगम मंडल और अन्य जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, उनमें रंग रोगन में गोबर से बने प्राकृतिक पेंट का इस्तेमाल होगा।



मुख्यमंत्री के इस फैसले का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने स्वागत किया है। श्री गडकरी ने ट्रीट कर लिखा है कि छत्तीसगढ़ के सरकारी विभागीय निर्माण में गोबर से बने प्राकृतिक पेंट के इस्तेमाल का निर्देश छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया है, उनके इस फैसले का अभिनंदन करता हूं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये फैसला सराहनीय और स्वागत योग्य है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने भी ट्रीट करते हुए केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी को धन्यवाद देते हुए कहा है कि नेक इरादों से ही देश और प्रदेश दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। श्री बघेल ने कहा है कि गोधन और श्रम का सम्मान कर छत्तीसगढ़ गांधी जी के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। कई मंचों पर छत्तीसगढ़ सरकार की इस योजना की तारीफ खुद प्रधानमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री कर चुके हैं। इसके अलावा इस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। यहां तक की इस योजना के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए कई राज्य अपने यहां के अधिकारियों को भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर भेज चुके हैं।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी शासकीय विभागों, निगम-मंडलों एवं स्थानीय निकायों में भवनों के रंग-रोगन के लिए गोबर पेंट का अनिवार्यतः उपयोग करने के निर्देश दिये हैं। पूर्व में जारी किए गए निर्देशों के बावजूद अभी भी निर्माण विभागों द्वारा केमिकल पेंट का उपयोग किए जाने पर नाराजगी जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि निर्देशों का उल्लंघन करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने मुख्य सचिव को सभी विभागों, निगम-मंडलों और स्थानीय निकायों को भवनों के रंगरोगन के लिए गोबर पेंट का उपयोग अनिवार्यतः करने के निर्देश जारी करने को कहा है। श्री बघेल ने कहा है कि गोबर पेंट का उपयोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण और पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होगा।

म्यूचुअल फंड के शुल्क पर लगाम की तैयारी



सेबी ने एक बयान में कहा कि नीति निर्माण के लिए इनपुट के रूप में ये अध्ययन आंकड़े प्रदान करने का प्रयास करेगा। इस अध्ययन के बाद बनाई जाने वाली नीतियां वित्तीय समावेशन को सुविधाजनक बनाने का प्रयास करेंगी। इसके साथ ही बाजार में जुड़ने वाले नए प्रतिभागियों या भागीदारों को प्रोत्साहित करने की कोशिश करेंगी। उल्लेखनीय है कि बाजार में छोटे निवेशकों की तेजी से बढ़ रही भागीदारी के महेनजर कई कदम उठाए गए हैं।

नई तकनीक अपनाने पर जोर देहेगा

इसके अलावा से इस अध्ययन से बढ़े पैमाने पर अर्थव्यवस्थाओं का लाभ उठाने की सुविधा मिलेगी। नई टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। इससे स्क्रीम्स में क्रॉस सब्सिडी को हतोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा किसी भी प्रकार के गलत व्यवहार पर अंकुश लगा कर संतुलन का प्रयास किया जाएगा। इसका मकसद निवेशकों का हित सुरक्षित करना है।

नई दिल्ली, बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने म्यूचुअल फंड्स द्वारा निवेशकों से वसूले जाने वाले शुल्क और खर्च का अध्ययन करना शुरू किया है ताकि उन पर लगाम लगाई जा सके। इस अध्ययन के आधार पर यदि जरूरी होगा तो सार्वजनिक परामर्श के बाद भागीदारों की प्रक्रिया में बदलाव के साथ-साथ उचित नीतिगत उपाय भी किए जाएंगे।

म्यूचुअल फंड उद्योग के लिए 2022 सुस्त रहा

म्यूचुअल फंड उद्योग पिछले साल के शानदार प्रदर्शन को वर्ष 2022 में दोहरा नहीं सका और पूरे साल बाजार में उतार-चढ़ाव रहने से उद्योग अपने संपत्ति आधार और निवेशकों की संख्या में बढ़ोतारी की रफ्तार बरकरार नहीं रख सका। हालांकि विश्लेषकों को उम्मीद है कि नया साल इस उद्योग के लिए अपेक्षाकृत बेहतर साबित होगा।



मोटापे पर नियंत्रण पाने में गददगार जीन खोजा

दावा सीआरटीसी -1 जीन हटाने से खाने की इच्छा कम होगी

ओसाका (जापान). अगर आप चिप्स, आइसक्रीम या चॉकलेट खाने की अपनी इच्छा को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए आपके मस्तिष्क में पाया जाने वाला एक जीन जिम्मेदार है. जापानी शोधकर्ताओं ने मस्तिष्क में एक ऐसे जीन की भूमिका की पहचान की है, जिसके कारण खाने की अधिक इच्छा होती है और इंसान अधिक खाने लगता है. यदि इस जीन को हटा दिया जाए तो इंसान के ज्यादा खाने की इच्छा कम हो जाती है.

शोधकर्ताओं ने बताया, कि यह जीन ही लोगों को बार-बार बिना भूख के खाने के लिए प्रेरित करता है, जिसकी वजह से लोगों का वजन बढ़ रहा है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बढ़ रही हैं. शोध के निष्कर्ष बताते हैं कि मोटापा बढ़ाने में इस जीन की बहुत ज्यादा भूमिका होती है.

शोध में यह स्पष्ट हो गया कि सीआईबी - रेगुलेटेड ट्रांसक्रिप्शन को एक्टीवेटर-1 (सीआरटीसी-1) नामक जीन मनुष्यों में मोटापे से जुड़ा है. शोध के दौरान जब चूहों में से सीआरटीसी-1 को हटा दिया गय, तो उनमें खाने की इच्छा कम होने लगी. सीआरटीसी-1 मस्तिष्क के सभी न्यूरॉन्स में पाए जाते हैं. यह शोध एफएसईबी जर्नल में प्रकाशित किया गया.

न्यूरॉन्स पर केंद्रित किया ध्यान

ओसाका मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर शिगेनोबु मात्सुमुरा के नेतृत्व में शोध समूह ने मेलानोकोर्टिन-4 रिसेप्टर (एमसी-4आर) को व्यक्त करने वाले न्यूरॉन्स पर ध्यान केंद्रित किया. उन्होंने पाया कि एमसी-4आर को व्यक्त करने वाले न्यूरॉन्स में सीआरटीसी-1 अधिक होने से खाने की इच्छा अधिक होती है और यही मोटापे का कारण बनता है.

इंसानों ने समझ पैदा होगी

शोधकर्ताओं ने कहा, इस जीन के कारण ही उच्च कैलोरी वाले खाद्य पदार्थ लेने का मन होता है, जिससे मोटापा और बड़ी स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं. शोधकर्ता मात्सुमुरा ने कहा, इस शोध से मस्तिष्क में सीआरटीसी-1 जीन की भूमिका का पता चला है. मात्सुमुरा ने कहा, हमें उम्मीद है कि इससे बेहतर समझ पैदा होगी कि लोगों के ज्यादा खाने का क्या कारण है?



अर्थव्यवस्था पर मोटापे का असर

मोटापे का अर्थव्यवस्था पर भी असर हो रहा है. भारत में 2019 में मोटापे पर खर्च 1.72 लाख रुपये था, जो जीडीपी का 0.8 प्रतिशत था. 2060 में ये 35.92 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा, जो जीडीपी का 2.75 होगा. मोटापे का अर्थ है बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स 30 से अधिक होना.

गंगीट बीमारियों की बना वजह

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मोटापे की वजह से दुनियाभर में लोग डायबिटीज, कैंसर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं. पहले के समय में मोटापा सिर्फ उच्च आय वाले देशों की समस्या थी, लेकिन अब मोटापा निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लोगों में भी बढ़ता जा रहा है.



दिल के मरीजों को कॉफी पीने से मौत का जोखिम

वाशिंगटन. काफी पीना कुछ मामलों में फायदेमंद होता है, लेकिन अब अमेरिकी शोधकर्ताओं ने एक शोध में बताया, प्रतिदिन दो या अधिक कप कॉफी पीना गंभीर उच्च रक्तचाप वाले लोगों में हृदय रोग से मृत्यु के जोखिम को दोगुना कर सकता है।



अध्ययन के निष्कर्ष जर्नल ऑफ द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन में प्रकाशित हुए थे। साथ ही अध्ययन में यह भी बताया गया कि हर दिन एक कप कॉफी या एक कप ग्रीन टी पीने से किसी भी रक्तचाप माप पर हृदय रोग से मरने का खतरा नहीं होता है।

हालांकि इससे पहले हुए एक शोध में बताया गया था कि एक दिन में एक कप कॉफी पीने से दिल का दौरा पड़ने के बाद मौत के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है और स्वस्थ व्यक्तियों में दिल के दौरे या स्ट्रोक को रोका जा सकता है। नए अध्ययन का उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि क्या कॉफी का ज्ञात सुरक्षात्मक प्रभाव उच्च रक्तचाप की विभिन्न डिग्री वाले व्यक्तियों पर भी लागू होता है। साथ ही शोधकर्ताओं ने एक ही आबादी में ग्रीन टी के प्रभावों की भी जांच की।

अध्ययन के वरिष्ठ लेखक हिरोयासु इसो ने कहा, यह इस तरह का पहला अध्ययन है, जिसमें प्रतिदिन 2 या अधिक कप कॉफी पीने और गंभीर उच्च रक्तचाप वाले लोगों में हृदय रोगियों में मृत्यु दर के बीच संबंध खोजने का प्रयास किया गया है।



राम सेतु मामला CM भूपेश बघेल ने कहा देश से माफी मांगे BJP

रायपुर: पौराणिक कथाओं के मुताबिक भारत और श्रीलंका के बीच जो समुद्र में पुल बना है, वो रामसेतु है। इसे लेकर कई तरहों की बहस होती रही है। अब केंद्र ने इसे लेकर संसद में जवाब दिया है कि रामसेतु के वजूद के कोई सबूत अभी नहीं मिले हैं। अब इसे लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है।

राम सेतु को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। सीएम बघेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने देशवासियों को गुमराह किया गया है। अब इस बयान से खुद कटघरे में खड़े हो गए हैं। सीएम बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इनका चरित्र है राम नाम जपना पराया माल अपना। जब कांग्रेस सरकार में ये बात कही गई थी तो तब हम राम विरोधी थे। अब उनकी सरकार सदन में कहती हैं, पुख्ता सबूत नहीं है, इनको किस श्रेणी में रखा जाए? आरएसएस और भाजपा के नेताओं को अब खुद अपनी सरकार से सवाल पूछना चाहिए।

राम सेतु को लेकर क्या कहा केंद्र ने

केंद्र सरकार की तरफ से रामसेतु पर जवाब देते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि हमारी कुछ सीमाएं हैं। क्योंकि ये करीब 18 हजार साल पहले का इतिहास है। जिस ब्रिज की बात हो रही वो करीब 56 किलोमीटर लंबा था। स्पेस टेक्नोलॉजी के जरिए हमने पता लगाया कि समुद्र में पत्थरों के कुछ टुकड़े पाए गए हैं, इनमें कुछ ऐसी आकृति है जो निरंतरता दिखाती है। समुद्र में कुछ चुना पत्थर और आईलैंड जैसी चीजें दिखी हैं। सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये कहना मुश्किल है कि रामसेतु का वास्तविक रूप वहां मौजूद है।

भारत जोड़ो यात्रा से घबराई बीजेपी

चीन में बढ़ते कोरोना के मामले के बीच भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की राहुल गांधी को लिखी भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित करने की चिट्ठी के बाद से ही कांग्रेस की यात्रा को लेकर संशय जारी है। वर्ही इस सब के बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान समाने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार घबराई हुई है। प्रोटोकॉल जारी केवल राहुल गांधी के यात्रा के लिए ही किया है। भूपेश बघेल ने कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना चीन में फैला हुआ है। चीन से जो फ्लाइट आ रही है, चीन से जो लोग आ रहे हैं। उनके रोकथाम के लिए कोई चिंता नहीं है। या प्रोटोकॉल के लिए कोई चिंता नहीं है। यह तो सीधी बात है कि केंद्र सरकार राहुल गांधी के यात्रा से घबराई हुई है।



प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के मिलेट मिशन को सराहा कहा - रायपुर में खोलें मिलेट - कैफे

छत्तीसगढ़ के कई मुद्दों को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने की मुलाकात

रायपुर। छत्तीसगढ़ के हितों से जुड़े मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब एक घंटे तक चर्चा हुई। इस दौरान सीएम ने पीएम को राज्य सरकार की उपलब्धियों के साथ समर्स्याएं भी बताई। इसके साथ ही

मुख्यमंत्री ने राज्य में संचालित मिलेट मिशन के संबंध में जानकारी दी। पीएम ने मिलेट मिशन की तारीफ करते हुए कहा कि रायपुर में मिलेट कैफे शुरू करें। सीएम ने पीएम को बताया कि छत्तीसगढ़ में मिलेट का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है। देश का पहला मिलेट बैंक की शुरुआत छत्तीसगढ़ में की गई है, जहां 22 प्रकार के मिलेट का उत्पादन होता है।

2024 में राहुल के नेतृत्व में लड़ना चाहिए चुनाव

एक प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री बघेल ने कहा, सारे विषय की तरफ से मैं कोई अधिकृत नहीं हूं, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता के नाते आप पूछेंगे तो, हाँ वर्ष 2024 में राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार के रूप में लाना चाहिए और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए।



सीएम ने की प्रधानमंत्री की तारीफ

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री की तारीफ की है। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ के कुछ मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री से समय मांगा था, लेकिन कल जिस प्रकार से प्रधानमंत्री की माता का निधन हुआ, तो मैंने पीएमओ से कार्यक्रम आगे बढ़ाने की बात कहीं। इसके बाद वहां से खबर आई कि प्रधानमंत्री अपना कोई कार्यक्रम स्थगित नहीं कर रहे हैं। किसी के घर में इस प्रकार से घटना घट जाए और इसके बाद भी लगातार अपने कार्यक्रम जारी रखे, ऐसे विरले ही उदाहरण देखने को मिलते हैं।

एमएसपी कोदो-कुटकी पर भी दे

मुख्यमंत्री बघेल ने केंद्र सरकार से कोदो कुटकी का भी समर्थन मूल्य घोषित करने की मांग की है। प्रधानमंत्री को भूपेश ने बताया कि हमने राज्य में कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य 3 हजार रुपए किंवंटल घोषित किया है। अब केंद्र सरकार को एमएसपी तय कर देना चाहिए। सीएम ने यह भी कहा कि जीएसटी से छत्तीसगढ़ को भी वाणिज्यिक कर राजस्व में कमी का सामना करना पड़ रहा है।



कोल ब्लॉक के 4170 करोड़ मांगे

सीएम भूपेश ने कहा- सुप्रीम कोर्ट में 2014 में निरस्त कोल ब्लॉकों से केंद्र सरकार को मिली एडिशनल लेबी यानी लगभग 4170 करोड़ रुपए की राशि को छत्तीसगढ़ को देनी चाहिए। उन्होंने पीएम से कहा कि केंद्र सरकार से कई बार अनुरोध कर चुके, लेकिन राशि नहीं मिली।

नये साल में सीएम भूपेश बघेल ने दी 4 बड़ी सौगातें

श्री भूपेश बघेल
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

डॉ. शिवकुमार डहरिया
माननीय श्रम मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन

सीएम ने श्रमिकों के साथ मनाया नये साल का जश्न
श्रमिक सहायता योजना की राशि 10 हजार बढ़ाई
सीएम ने कहा- मजदूर बच्चों को मिलेगी फ्री कोचिंग

रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को नये साल की बधाई दी है। सीएम ने साल के पहले दिन बड़ी घोषणा करते हुए प्रदेश के श्रमवीरों को सौगात दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चावड़ी पहुंचकर श्रमिकों से मुलाकात की और कहा कि अब मजदूर के बच्चे मजदूर नहीं रहेंगे। हमारी सरकार आपके साथ है। इतना ही नहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्रमिकों के बच्चों को निशुल्क कोचिंग देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर में श्रमिकों से मुलाकात करते हुए श्रमिक सहायता योजना की राशि को 10 हजार से से बढ़ाकर 20 हजार करने की घोषणा की है। इसके साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए श्रमिकों के बच्चों को निशुल्क कोचिंग देने की घोषणा की है।

सीएम ने कहा- चौथी-पांचवीं के बच्चों को सैनिक स्कूल, नवोदय में एडमिशन के लिए लिए भी कोचिंग और आधारभूत प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। सीएम ने कहा कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, जिससे हर किसी के जीवन में प्रकाश आ जाता है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने श्रमवीरों को श्रमिक सियान योजना के तहत 10 हजार की सहायता राशि वितरित की है।

4 नई सौगातें

मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए संचालित मेघावी छात्र छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना के नाम में परिवर्तन करते हुए मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेघावी शिक्षा योजना करने की घोषणा की। इस योजना के तहत मुख्यमंत्री ने नवीन कोर्स जैसे इंजीनियरिंग, आईआईटी, बीटेक, ट्रिपल आईटी, एमटेक, एमबीबीएस इत्यादि की पढ़ाई सहित विदेशों में अध्ययन करने के लिए भी श्रमिकों के बच्चों को सहायता देने की घोषणा की। उन्होंने इन सभी पाठ्यक्रमों में पढ़ाई करने के लिए श्रमिकों के बच्चों को प्रवेश शुल्क, शैक्षणिक शुल्क, आवास एवं भोजन शुल्क में सहायता प्रदान करने के साथ ही प्रतिवर्ष स्टेशनरी के लिए भी 2 हजार रूपए की सहायता देने की घोषणा की है।

कंबल और मिठाई भी की वितरित

सीएम भूपेश बघेल ने निर्माण श्रमिक उत्कृष्ट खेल के लिए बच्चों को 40 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सबको को नए वर्ष पर कंबल और मिठाई भी वितरित की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना के तहत संचालित भोजन केंद्र में श्रमिकों के साथ नाश्ता भी किया है। इसके साथ ही श्रमिक भाई बहनों के साथ चर्चा की गई और व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया।



नए साल की वो 5 उम्मीदें जो सपनों को देंगी उड़ान

रायपुर : 2022 की विदाई हो चुकी है. नया साल 2023 आ गया है. नए साल में लोगों को नई उम्मीदें और नए सपने हैं. 2023 में छत्तीसगढ़ वासियों को नई उम्मीदें हैं. ये उम्मीद रोजगार, शिक्षा, हेल्थ से जुड़ी हैं. 2023 में राज्य में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं. इस बार 18 साल की उमआ पूरे कर चुके युवा पहली बार मतदान करेंगे. इसके साथ-साथ ही राज्य की प्रगति के लिए सरकार कई अहम फैसले ले सकती है.

धान का समर्थन मूल्य बढ़ेगा

छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है. अभी किसान 2500 रुपए के समर्थन मूल्य में अपनी धान बेच रहे हैं. किसानों को उम्मीद है कि नए साल में सरकार एक बार फिर से समर्थन मूल्यों में वृद्धि कर सकती है. इसके साथ ही प्रदेश के किसानों को सरकार को कई बड़ी राहतें मिलने की भी उम्मीदें हैं.

आत्मानंद स्कूल की संख्या में बढ़ोतारी

शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रदेशवासियों को बड़ी उम्मीदें हैं. छत्तीसगढ़ में प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने आत्मानंद स्कूलों को बढ़ाकर बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए काम कर रही है. सरकार का मुख्य उद्देश्य बेहतर शिक्षा के साथ-साथ बच्चों को आने वाले भविष्य में रोजगार के लिए कैपेबल बनाना है. ऐसे में माना जा रहा है कि नए साल में नए आत्मानंद स्कूल ओपन होंगे.

आरक्षण विधेयक को मंजूरी

छत्तीसगढ़ में नए साल में सबसे ज्यादा उम्मीद लोगों को आरक्षण से है. माना जा रहा है कि राज्यपाल आरक्षण विधेयक पर साइन कर देंगी. जिसके बाद प्रदेश में नई आरक्षण व्यवस्था लागू हो जाएगी. बता दें कि आरक्षण विधेयक विधानसभा में सर्वसम्मति से पास हो चुका है और राज्यपाल के पास साइन के लिए भेजा गया है.



ओल्ड पेंशन योजना के प्रयास में तेजी

छत्तीसगढ़ की सरकार लगातार ओल्ड पेंशन योजना को लेकर काम कर रही है. इससे छत्तीसगढ़ में शासकीय कर्मचारियों के साथ-साथ नए कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सकेगा. लगातार प्रदेश की सरकार केंद्र सरकार से चर्चा करते हुए प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना से जोड़ते हुए उनकी नई पेंशन योजना का पैसा दिलाने को लेकर काम कर रही है.

बेरोजगार युवाओं के लिए नई योजना

छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर कम है. नए साल में लोगों को रोजगार की सबसे ज्यादा उम्मीद है. युवाओं के लिए नए-नए रोजगार के साधन उपलब्ध कराने में सरकार भी प्रयासरत है. माना जा रहा है कि नए साल में प्रदेश के अलग-अलग विभागों में नई-नई वैकेंसी निकल सकती है.

देश का इकलौता राज्य छत्तीसगढ़ जहां समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा मिलेट्स

रायपुर. छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन के चलते राज्य में कोदो, कुटकी और राणी (मिलेट्स) की खेती को लेकर किसानों का रझान बहुत तेजी से बढ़ा है। पहले औने-पौने दाम में बिकने वाला मिलेट्स अब छत्तीसगढ़ राज्य में अच्छे दामों में बिकने लगा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विशेष पहल के चलते राज्य में मिलेट्स की समर्थन मूल्य पर खरीदी होने से किसानों को करोड़ों रुपए की आय होने लगी है। बीते सीजन में किसानों ने समर्थन मूल्य पर 34298 किंवंटल मिलेट्स 10 करोड़ 45 लाख रुपए में बेचा था। छत्तीसगढ़ देश का इकलौता राज्य है, जहां कोदो, कुटकी और राणी की समर्थन मूल्य पर खरीदी और इसके वैल्यू एडिशन का काम भी किया जा रहा है। कोदो-कुटकी की समर्थन मूल्य पर 3000 प्रति किंवंटल की दर से तथा राणी की खरीदी 3377 रुपए प्रति किंवंटल की दर से खरीदी की जा रही है।

डॉ. दानेश्वरी संभाकर
सहायक संचालक



कोदो-कुटकी उगाने वाले किसान समृद्धि की ओर

शासन की महत्वाकांक्षी योजना राजीव गांधी किसान न्याय योजना एवं मिलेट मिशन किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा वर्ष 2021-22 में 5,273 टन मिलेट जिसका मूल्य ₹. 16.03 करोड़ का समर्थन मूल्य पर क्रय किया गया है। वर्ष 2022-23 में 13,005 टन मिलेट जिसका मूल्य ₹. 39.60 करोड़ का समर्थन मूल्य पर क्रय करने का लक्ष्य है।

देश के कई आदिवासी इलाकों में मोटे अनाज का काफी समय से प्रयोग किया जाता रहा है। यह स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत फायदेमंद है, इसलिए अब दूसरे इलाकों में भी इन अनाज का काफी इस्तेमाल किया जा रहा है। एक्सपर्ट के मुताबिक कोदो कुटकी को प्रोटीन व विटामिन युक्त अनाज माना गया है। इसके सेवन से शुगर बीपी जैसे रोग में लाभ मिलता है। कोदो एक मोटा अनाज है, जिसे अंग्रेजी में कोदो मिलेट या काउ ग्रास के नाम से जाना जाता है। कोदो के दानों को चावल के रूप में खाया जाता है और स्थानीय बोली में भगर के चावल के नाम पर इसे उपवास में भी खाया जाता है। बस्तर के आदिवासी संस्कृति व खानपान में कोदो कुटकी राणी जैसे फसलों का महत्वपूर्ण स्थान है।



छत्तीसगढ़ राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के सहयोग एवं मार्गदर्शन से किसान कोदो के प्रमाणित बीज का उत्पादन कर अच्छा खासा मुनाफा अर्जित करने लगे हैं। बीते एक सालों में प्रमाणित बीज उत्पादक किसानों की संख्या में लगभग 5 गुना और

किसानों की संख्या और बीज विक्रय से होने वाला लाभ कई गुना बढ़ गया है। बीते तीन वर्षों में कोदो प्रमाणित बीज उत्पादक किसानों ने एक करोड़ 65 लाख 18 हजार 633 रूपए का बीज, छत्तीसगढ़ बीज एवं विकास निगम को विक्रय किया है।

2022 सम्मान भी मिल चुका है। राज्य में मिलेट्स उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इसको राजीव गांधी किसान न्याय योजना में शामिल किया गया है। मिलेट्स उत्पादक कृषकों को प्रोत्साहन स्वरूप प्रति एकड़ के मान से 9 हजार रूपए की आदान सहायता भी दी जारही है।

राज्य में कोदो, कुटकी और रागी की खेती को राज्य में लगातार विस्तारित किया जा रहा है, जिसके चलते राज्य में इसकी खेती का रकबा 69 हजार हेक्टेयर से बढ़कर एक लाख 88 हजार हेक्टेयर हो गया है। मिलेट की खेती को प्रोत्साहन, किसानों को प्रशिक्षण, उच्च क्वालिटी के बीज की उपलब्धता तथा उत्पादकता में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए राज्य में मिलेट मिशन संचालित है। 14 जिलों ने आईआईएमआर हैदराबाद के साथ छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के प्रयास से मिलेट मिशन के अंतर्गत त्रिपक्षीय एमओयू भी हो चुका है। छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन के तहत मिलेट की उत्पादकता को प्रति एकड़ 4.5 किवंटल से बढ़ाकर 9 किवंटल यानि दोगुना किए जाने का भी लक्ष्य रखा गया है।



इससे होने वाली आय में चार गुना की वृद्धि हुई है। वर्ष 2021-22 में राज्य के 11 जिलों के 171 कृषकों द्वारा 3089 किवंटल प्रमाणित बीज का उत्पादन किया गया, जिसे बीज निगम ने 4150 रूपए प्रति किवंटल की दर से किसानों से क्रय कर उन्हें एक करोड़ 28 लाख 18 हजार रूपए से अधिक की राशि भुगतान किया है। राज्य के किसानों द्वारा उत्पादित प्रमाणित बीज, सहकारी समितियों के माध्यम से बोआई के लिए प्रदाय किया जा रहा है।

बीज प्रमाणीकरण संस्था के अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2020-21 में राज्य में 7 जिलों के 36 किसानों द्वारा मात्र 716 किवंटल प्रमाणित बीज का उत्पादन किया गया था। इससे उत्पादक किसानों को 32 लाख 88 हजार रूपए की आमदनी हुई थी, जबकि 2021-22 में कोदो बीज उत्पादक

अधिकारियों ने बताया कि ऐसी कृषि भूमि जहां धान का उत्पादन नाममात्र उत्पादन होता है, वहां कोदो की खेती किया जाना ज्यादा लाभकारी है। कोदो की खेती की कम पानी और कम खाद की जरूरत पड़ती है। जिसके फलस्वरूप इसकी खेती में लागत बेहद कम आती है और उत्पादक कृषकों को लाभ ज्यादा होता है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019-20 में राज्य में मात्र 103 किवंटल प्रमाणित बीज उत्पादन हुआ था। मिलेट्स मिशन लागू होने के बाद से छत्तीसगढ़ राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा अन्य शासकीय संस्थानों से समन्वय कर कोदो बीज उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है, जिससे बीज उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है। गौरतलब है कि मिलेट्स की खेती को बढ़ावा देने के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य को राष्ट्रीय स्तर का पोषक अनाज अवार्ड



नई दिल्ली, नए अध्ययन से पता चला है कि कोरोना वायरस इंसानों के दिमाग सहित पूरे शरीर में फैल सकता है। कोविड-19 से मरने वाले 44 लोगों की ऑटोप्सी से ऊतक के नमूनों के विश्लेषण से पता चला है कि वायरस मस्तिष्क सहित पूरे शरीर में फैल गया था और यह लगभग आठ महीने तक बना रहा।

आठ महीने तक शरीर में यह सकता है कोरोना संक्रमण



इन मरीजों ने कोरोनारोधी टीका नहीं लिया था, जिनकी जांच की गई उनमें 38 के रक्त प्लाज्मा का टेस्ट पॉजिटिव मिला था, तीन रोगियों का टेस्ट निगेटिव रहा जबकि तीन के खून का प्लाज्मा उपलब्ध नहीं था।

विश्लेषण के अनुसार कोरोना वायरस ने बड़े पैमाने पर फेफड़े और सांस की नली के ऊतकों को संक्रमित और नुकसान पहुंचाया। लेकिन शोधकर्ताओं ने 84 अलग-अलग शरीर के स्थानों और शारीरिक तरल पदार्थों में वायरस का वायरल आरएनए भी पाया। शोधकर्ताओं ने एक मरीज के हाइपोथ्रैलेमस और सेरिब्रल में और दो अन्य रोगियों की रीढ़ की हड्डी और बेसल गैनिल्या में कोरोना वायरस और प्रोटीन का पता लगाया। लेकिन उन्हें मस्तिष्क के ऊतकों को बहुत कम नुकसान हुआ था। अध्ययनकर्ता डैनियल चेरटो ने कहा कि पहले सोच यह थी कि कोरोना मुख्य रूप से श्वसन वायरस था, लेकिन ऐसा नहीं है।

मरीजों की औसत आयु 62.5 साल

जिन रोगियों पर अध्ययन किया गया उनकी औसत आयु 62.5 साल थी। इनमें 30 महिलाएं थीं। 27 मरीजों को तीन या अधिक बीमारियां पहले से थीं। अध्ययन में यह सामने आया कि इन मरीजों में कोरोना के लक्षण शुरू होने के औसत 18.5 दिनों के अंदर मौत हो गई। कई गैर-श्वसन स्थलों में लक्षणों की शुरुआत के बाद पहले दो हफ्तों के दौरान वायरस को बदलते हुए भी देखा गया।

अमेरिका में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का अध्ययन

अमेरिका में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने अप्रैल 2020 और मार्च 2021 के बीच हुई ऑटोप्सी से लिए गए नमूनों का विश्लेषण किया। नेचर जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार शोधकर्ताओं ने 11 रोगियों के मस्तिष्क सहित पूरे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम नमूना लिया।



सोनमती ने लिखी आत्मनिर्भरता की नई कहानी, मशरूम की खेती कर कमाए 7 लाख रुपये

रायपुर. हौसले और हुनर को निखरने के लिए अवसर की तलाश होती है. छत्तीसगढ़ की मेहनती महिलाओं को ऐसा ही अवसर गौठानों में बनाए गए मल्टीएक्टिविटी सेंटर दे रहे हैं. इससे वे आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख रही हैं. इन्हीं में से बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के ग्राम बसन्तपुर के गौठान में संचालित सामुदायिक बाड़ी में काम करने वाली आकाश महिला स्व-सहायता समूह की सदस्य श्रीमती सोनमती कुशवाहा भी हैं, जिन्होंने मशरूम उत्पादन कर पिछले 3 वर्षों में 7 लाख रुपये कमाए हैं. इससे उन्हें न सिर्फ आत्मविश्वास बढ़ा है, बल्कि वह परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा कर पाने में सक्षम हो गई हैं.

गैरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा हमेशा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की रही है. इसके लिए गौठानों को मल्टीएक्टिविटी सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है. यहां महिला स्व-सहायता समूह की महिलाओं को आजीविका संवर्धन के लिए प्रशिक्षण दे कर स्वावलंबन की राह बताई जा रही है.

इसी कड़ी में बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में महिला समूहों को उद्यान विभाग द्वारा प्रशिक्षण, मार्गदर्शन देकर मशरूम उत्पादन हेतु निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है. विभाग द्वारा मशरूम की खेती के लिए आवश्यक सामग्री जैसे- बीज, पॉलीथीन बैग्स, चाक पाउडर भी महिलाओं को उपलब्ध कराए जा रहे हैं. इससे बसन्तपुर गौठान के सामुदायिक बाड़ी में कार्यरत आकाश महिला स्व-सहायता समूह की महिलाएं भी अब मशरूम की खेती, मधुमक्खी पालन और कश्मीरी मिर्च का उत्पादन कर स्वावलंबी बन रही हैं.

आकाश महिला समूह की सदस्य श्रीमती सोनमती कुशवाहा बताती हैं कि पहले वे सामान्य खेती-बाड़ी करके जीवन यापन करती थीं. इससे उन्हें परिवार के पालन-पोषण, बच्चों की पढ़ाई-लिखाई का खर्च वहन करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था. मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी सुराजी ग्राम योजना के तहत बसन्तपुर में गौठान खुला और बिहान के माध्यम से जुड़ने का मौका मिला. इसके बाद गौठान में उन्हें उद्यान विभाग द्वारा मशरूम उत्पादन, कश्मीरी मिर्च की खेती, मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण दिया गया.



समूह से लोन लेकर घर पर ही शुरू की मशरूम खेती

श्रीमती सोनमती कुशवाहा ने बताया कि उन्होंने समूह से 60 हजार रुपये का लोन लेकर घर पर ही मशरूम की खेती की और शुरूआती दौर में ही 2 लाख रुपये की आमदानी हुई. इससे उनके हौसले को नई उड़ान मिली. इसके बाद उन्होंने मधुमक्खी पालन और कश्मीरी मिर्च की खेती का कार्य भी प्रारंभ किया और मधुमक्खी पालन से उन्होंने 60 किलोग्राम शहद का उत्पादन कर 70 हजार रुपए आर्थिक आमदानी प्राप्त की. श्रीमती कुशवाहा ने बताया कि मशरूम की खेती से प्रतिदिन 20 से 30 किलो मशरूम का उत्पादन हो रहा है, जिसे बेचकर विगत 3 वर्षों में 7 लाख रुपये की आय अर्जित की है तथा अपने परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा कर रही है.





**लक्ष्य का 35% पूरा, 2023 में 100 प्रतिशत पूरा करने का अनुमानः कैबिनेट मंत्री
जल जीवन मिशन के तहत 17 लाख से अधिक
परिवारों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराएँ :
मंत्री गुरु लद्द कुमार**

रायपुर, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कैबिनेट मंत्री जगतगुरु गुरु लद्द कुमार ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी का कार्यभार संभाला. सरकार बनते ही आम जनता की मांग और पानी की समस्या को देखते हुए उन्होंने सर्वप्रथम मिनीमाता योजना की शुरुआत की. इस योजना के तहत ग्रामीण अंचलों में हर घर नल से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा जिसे वे लगातार पूरा करते गए करीब 5 लाख

50 हजार से अधिक परिवारों तक नल कनेक्शन उपलब्ध कराया गया. जिसके बाद केंद्र सरकार की योजना लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी अंतर्गत जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई. तत्पश्चात राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत मिनीमाता योजना के कार्यों को सम्मिलित किया. और इसी उद्देश्य से हर घर नल से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य पूरा किया जा रहा है.

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत जल जीवन मिशन के कार्यों को छत्तीसगढ़ में तेजी से क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रदेश में अभी तक लगभग 3000 करोड़ से अधिक के कार्यों की कार्य आदेश जारी किए जा चुके हैं और कई ग्राम पंचायतों में कार्य पूरे हो चुके हैं। प्रदेश में अब तक 35% से भी अधिक कार्य पूर्ण हो चुके हैं। इस बात की खुशी है कि प्रदेश के 17 लाख से अधिक परिवारों को शुद्ध नल से जल प्रदान किया जा रहा है। इस साल लगभग 100% घरों में नल कनेक्शन करने का लक्ष्य है जिसे हम जरूर पूरा करेंगे। प्रदेश के सभी जिलों में इस योजना की शुरुआत हो चुकी है कई ऐसे जगह हैं जहां अभी टेंडर लग चुके हैं और कई ग्राम पंचायतों में आम जनता को शुद्ध पेयजल मिलना शुरू हो गया है।

सिंगल विलेज स्कीम, मल्टी विलेज स्कीम और सोलर पंप स्कीम के तहत घर-घर नल से शुद्ध पेयजल सप्लाई के लिए नल कनेक्शन का कार्य किया जा रहा है। हर ग्राम पंचायतों में सिंगल विलेज स्कीम के माध्यम से नल कनेक्शन दिया जा रहा है लगातार लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों द्वारा टेंडर जारी किए जा रहे हैं और अधिकारियों की निगरानी में सभी कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। ऐसे ही गांव में पानी के स्रोत नहीं मिल पारहै उनके लिए मल्टी विलेज स्कीम तैयार की गई है। मल्टी विलेज स्कीम के तहत 10-20 गांव, 50-100 गांवों को जोड़ कर स्कीम तैयार किया गया है अभी यह टेंडर प्रक्रियाधीन है। अगले महीने से ही इस पर काम शुरू कर दिए जाएंगे।

करीब 800 करोड़ से अधिक के कार्य सोलर पंप के माध्यम से नल कनेक्शन लगाए जा रहे हैं। जल्द ही 300 करोड़ के कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं इसे भी टेंडर लगाकर कार्य अनुबंध कराए जाएंगे। सोलर पंप के माध्यम से किए जा रहे कार्यों को क्रेडो के माध्यम से कराया जा रहा है जिसे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग समय-समय पर फंड उपलब्ध कराते हैं।



इन 4 सालों में जन संदेश यात्रा और गुरुदर्शन कार्यक्रम से सामाजिक मजबूती मिली : जगतगुरु गुरु रूद्र कुमार

रायपुर. जगतगुरु गुरु रूद्र कुमार छत्तीसगढ़ में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद समाज के एकजुट करने का प्रयास किया. समाज के हर वर्ग तक पहुंचने की कोशिश की. जन संदेश यात्रा और गुरुदर्शन कार्यक्रम के माध्यम से सभी वर्ग को परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी के बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया. समाज के सभी वर्गों की हर मांगों को पूरी करने की कोशिश की. समाज से जुड़ी तमाम बातों को प्रमुखता से आवाज दी. समाज के सभी वर्ग चाहे छात्र-छात्राएं हो, सामाजिक बंधु हो चाहे या जरूरतमंद सब की बात सुनी और उनकी समस्या का निराकरण करने का पूरा प्रयास किया.

समाज के लोगों को सामाजिक एकता, भाई-चारा, विश्व बंधुत्व और शांति का संदेश देने के साथ-साथ परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी के आदर्शों पर चलकर एक नया समाज गठित करने के लिए संकल्पित किया. बाबाजी के बतलाए रास्ते पर चलकर घमनखे-मनखे एक समानान्ष के धैयय को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के कई जिलों में सतनाम संदेश यात्रा निकाली गई. जिसका मुख्य उद्देश्य संत समाज को एकजुट रहने और सतनाम धर्म की ऐतिहासिकता, धार्मिक स्थलों में सामुदायिक सुविधाओं के विस्तार, संत संदेशों पर व्याख्यान, समाज के नीति-नियम, रीति-रिवाज, संस्कृति व संस्कार की एकरूपता एवं समाज की वर्तमान दशा और दिशा विषय पर बात की.



जगतगुरु गुरु रूद्र कुमार ने कहा कि सैकड़ों वर्ष पूर्व सतनाम पंथ के प्रथम प्रणेता परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास ने इस संसार में सत्य अंहिसा और शांति का संदेश दिया था, जिसका अनुसरण विश्व में किया जा रहा है. अपने धर्म संदेश के द्वारा उन्होंने सभी वर्गों, सम्प्रदायों एवं मानव समाज की एकता और भाईचारा पर विशेष जोर दिया. इस प्रकार उनके विचार युग-युगान्तर तक प्रारंभिक रहेंगे. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज के लोगों की बहुलता है. उन्होंने समाज के लोगों को एकजुट होने का आव्हान किया और कहा कि चाहे धर्म की बात हो, चाहे समाज के विकास की बात हो, एकता के साथ एक मंच पर सभी का खड़ा होना जरूरी है.



रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार जन हितैषी सरकार है, जनता की सेवा करना ही हमारा उद्देश्य है। इसी धैयय के साथ हम पूरे विधानसभा क्षेत्र में लगातार इमानदारी से कार्य करते रहें। या बात छत्तीसगढ़ गौरव दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार के 4 साल पूरे होने पर लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी और ग्रामोद्योग मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने कही।

विगत 4 साल में किए गए कार्यों की जानकारी देते हुए मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने कहा कि हमने अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के सभी ग्राम पंचायतों में सर्व समाज के लिए सामुदायिक भवनों का निर्माण, सीसी रोड, सड़क, नाली निर्माण, तालाबों का सौंदर्यकरण, पचरी निर्माण, अहाता निर्माण, सांस्कृतिक मंच, चबूतरा निर्माण, बोर खनन कार्य, मुक्तिधाम में शेड का कार्य, पाइप लाइन विस्तार का कार्य, पाइप टंकी का निर्माण, प्रतीक्षालय बनाने का कार्य, गौठान बनाने का कार्य, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पुल-पुलिया, नहर-नाली निर्माण का कार्य, समतलीकरण, पंचायत भवनों का जीर्णोद्धार, अटल समरसता भवन का निर्माण आदि अनेकों विकास कार्य प्राथमिकता से किया गया। इसके साथ ही बच्चों के भविष्य को संवारने उन्हें सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्राथमिक स्कूल, मिडिल स्कूल और हाईस्कूल के साथ-साथ कॉलेजों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार का कार्य किया गया।

कांग्रेस सरकार बनने के 4 साल में अहिवारा विधानसभा क्षेत्र को 350 सौ करोड़ से अधिक के विकास कार्य की मिली सौगात



इसके साथ ही छात्र एवं छात्राओं के लिए छात्रावास का निर्माण किया गया ताकि हमारे क्षेत्र के बच्चे हॉस्टल में ही रहकर अपनी पढ़ाई कर सकें। विधानसभा क्षेत्र के बानबरद में शासकीय महाविद्यालय के नवीन भवन का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के कर कमलों से भी किया गया। हमारी सरकार ने पिछले साल ही भिलाई-3 चरोदा नगर निगम को माननीय मुख्यमंत्री ने 41 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात देकर क्षेत्रवासियों को बड़ी सुविधा प्रदान की। आम जनता के स्वास्थ्य के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की गई अस्पतालों में बिस्तरों को बढ़ाया गया वेंटिलेटर की सुविधा दी गई पूरे विधानसभा क्षेत्रों में एंबुलेंस की शुरुआत की गई ताकि मरीजों को किसी तरीके की परेशानी ना हो। हर घर शुद्ध जल उपलब्ध कराने के लिए नल कनेक्शन लगाए गए। ग्रामोद्योग विभाग के अंतर्गत ग्रामीण अंचलों में श्रमिक परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराए गए।

मुख्य रूप से अहिवारा विधानसभा क्षेत्र में इन विकास कार्यों को कराया गया

- भिलाई-3 को नवीन तहसील की सौगात।
- अहिवारा को उप तहसील की सौगात मिली।
- अहिवारा विधानसभा क्षेत्र में तीन नई आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना की।
- जेवरा-सिरसा रोड चौड़ीकरण और नवीनीकरण का कार्य किया गया।
- बहुप्रतीक्षित नंदिनी-अहिवारा रोड का निर्माण कराया गया।
- भिलाई-3 में मिनी स्टेडियम को स्टेडियम के रूप में अपग्रेड करने की घोषणा की।
- जनता स्कूल स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम में सीट की बढ़ोत्तरी की घोषणा।
- बानबरद में चार करोड़ 83 लाख की लागत से नवीन शासकीय कॉलेज भवन का निर्माण कराया गया।
- चरौदा के फुटबाल स्टेडियम में सीटिंग स्टैंड के निर्माण।
- कुंदरापारा में सालों से कब्जा की गई स्टेडियम की जमीन को खाली कराया गया।
- कुन्दरापारा में विस्थापित लोगों को पट्टा देने और विस्थापित करने की व्यवस्था की गई।
- राजीव गांधी आश्रय योजना एवं मुख्यमंत्री आबादी पट्टा योजना के हितग्राहियों को पट्टों का वितरण किया।
- क्षेत्र में कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना किया गया।
- क्षेत्र में स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस और ईलाइब्रेरी की स्थापना की गई।

ग्रामोद्योग विभाग से ग्रामीण अंचल की महिलाओं और श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए दिया जा रहा प्रशिक्षण

ग्रामीण अंचल में रोजगार से सीधे जोड़ने का प्रयास कर रही है

ग्रामोद्योग विभाग

रायपुर. ग्रामोद्योग मंत्री गुरु रूद्र कुमार ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा वन आधारित ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के संकल्प की प्रतिमूर्ति हेतु कोसा रेशम योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

ग्रामोद्योग संचालित रेशम प्रभाग द्वारा संचालित योजनाओं का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अंचलों के स्थानीय ग्रामीण एवं विशेष तौर पर महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है रेशम प्रभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं से 220939 हितग्राहियों एवं श्रमिक लाभान्वित हो रहे हैं। वही कोरोना काल में 5 लाख से अधिक श्रमिक परिवारों को सीधे रोजगार से जोड़ा गया। ग्रामोद्योग विभाग लगातार ग्रामीण अंचलों में महिलाओं को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध कराने का कार्य कर रही है।



वेट रीलिंग सह प्रदर्शन केंद्र कोरबा में दो तसर वन बुनाई कलस्टर उमरेली एवं छुरी में है जहां लगभग 258 बुनकर परिवार तसर वस्त्र बुनाई एवं रंगाई कार्य में संलग्न हैं। बस्तर जिले में नवीन ककून बैंक नानगुर में स्थापित करने की घोषणा की गई है। माटी कला बोर्ड के माध्यम से नवंबर 2022 तक 1918 नग निशुल्क विद्युत चौक का वितरण किया गया जिसके माध्यम से 5754 हितग्राहियों को स्वरोजगार से जोड़ा गया।



माटी कला बोर्ड द्वारा वर्तमान समय में 3 ग्लेजिंग यूनिट संचालित हैं जिससे लगभग 700 माटीशिल्पी परिवार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हो रहे हैं। दंतेवाड़ा जिले के कुम्हाररास गांव में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा ग्लेजिंग यूनिट का शुभारंभ किया गया। नए ग्लेजिंग यूनिट में स्थानीय एवं आसपास के लगभग 300 माटी शिल्पी परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। नवंबर 2022 तक 9459 माटीशिल्पियों और कुंभकारों का पंजीयन किया गया।

आवासीय प्रशिक्षण योजना के तहत 377 माटीशिल्पीओं को प्रशिक्षित किया गया एवं ग्रीष्मकालीन में प्रशिक्षण के दौरान 73 स्कूली एवं कॉलेज के विद्यार्थियों को टेराकोटा का प्रशिक्षण दिया गया। माटीशिल्पीओं का प्रशिक्षण योजना के तहत 700 से अधिक माटीशिल्पीओं को प्रशिक्षित किया गया।



पूर्व मंत्री राजेश मूणत 'यूथ हब' को गलत तरीके से परिभ्रमित कर चौपाटी के नाम पर आम जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं: विकास उपाध्याय

रायपुर. नगर निगम रायपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत साईंस कॉलेज मैदान से लगे जगह पर यूथ हब बनाये जाने भाजपा के विरोध को लेकर क्षेत्रीय विधायक विकास उपाध्याय का बयान सामने आया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व मंत्री राजेश मूणत अपनी खोई जमीन तलाशने आम जनता को चौपाटी के नाम पर दिग्भ्रमित कर रहे हैं, जबकि अपने कार्यकाल में रोहणीपुरम के धन्यवाद मैदान को संघ के लिए आवंटित कर निर्माण कार्य करवा दिया। उन्होंने कहा, साईंस कॉलेज मैदान से लगे एक छोटे से भाग में चौपाटी नहीं बल्कि युवाओं के मंशा के अनुरूप व उनकी मांग के आधार पर यूथ हब बनाया जा रहा है, इस भाग में मैदान आ ही नहीं रहा है, जो निर्मित होने के बाद एजुकेशनल हब के अनुरूप होगा।

विधायक विकास उपाध्याय ने कहा, भाजपा के लोग कांग्रेस का आम जनता से कनेक्ट बर्दाशत नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरह से विगत 04 वर्षों में स्थानीय समस्याओं को लेकर पूरे पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में कारगर रूप से काम

हुआ है, उसका विरोध करने भाजपा के नेताओं को 04 साल तक कोई मुद्दा नहीं मिल पाया और अब जब चुनावी वर्ष का आगाज होने जा रहा है तो राजेश मूणत जबरदस्ती का सक्रीयता दिखाने विरोध की राजनीति कर क्षेत्र के विकास में अवरोध उत्पन्न करने आमादा है। उन्होंने रायपुर के साईंस कॉलेज मैदान से लगे भू-भाग पर नगर निगम रायपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अन्तर्गत यूथ हब का विरोध कर साबित कर दिया है कि भाजपा नहीं चाहती कि एजुकेशनल हब के बीच युवाओं को वह सारी सुविधाएँ उपलब्ध हो जो महानगरों की तर्ज पर मिलती है।

विकास उपाध्याय ने आगे कहा, पूर्व मंत्री राजेश मूणत अपने कार्यकाल के 15 वर्षों में लगातार उन प्रोजेक्ट पर काम किया, जिसमें हजारों करोड़ों का बजट हो ताकि इसका बन्दरबाट किया जा सके। साईंस कॉलेज मैदान में उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम बनवाकर सबसे पहले इस मैदान के क्षेत्रफल को खत्म कर दिया, जबकि इस स्टेडियम की यहाँ आवश्यकता ही नहीं थी। उन्होंने कहा कि इस स्टेडियम में पिछले 10 सालों में मात्र एकबार हॉकी खेला गया है और जबकि इसके खरखाव में लाखों रुपये सालाना खर्च हो रहे हैं। बावजूद कांग्रेस ने तात्कालीन सरकार का विरोध इसलिए नहीं किया कि राजधानी नये विकास के पथ पर अग्रसर है। रोहणीपुरम स्थित धन्यवाद मैदान को तमाम विरोध के बावजूद अपने प्रभाव का उपयोग कर संघ

के हवाले कर निर्माण कार्य करवा दिया और आज जब युवाओं की मंशा के अनुरूप अत्याधुनिक यूथ हब बनाने की मंशा को लेकर कांग्रेस कुछ करना चाह रही है तो इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया।

विकास उपाध्याय ने स्पष्ट शब्दों में कहा, वे पश्चिम विधानसभा क्षेत्र को विकसित क्षेत्र के रूप में अपग्रेड करना चाहते हैं। इसलिए इसकी सुंदरता व भव्यता कैसी हो को दृष्टिगत रखते हुए लगातार कार्य किये जा रहे हैं। आमानाका गेट से लेकर आमापारा तक जिस तरह से रोड के दोनों किनारों में अव्यवस्थित तरीके से टेले और गुमटियाँ संचालित होती हैं, इस बजह से ट्रैफिक पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। वह सब वे व्यवस्थित करने के पक्षधर हैं और यह सब करने भाजपा के विरोध का वह परवाह नहीं करते। इस क्षेत्र में अध्ययनरत उच्च शिक्षित युवाओं की मंशा थी कि उन्हें महानगर के तर्ज पर एक यूथ हब मिलना चाहिए और उसी के अनुरूप हम यह बनाने जा रहे हैं।



राजभवन-राज्य सरकार

के बीच बढ़ा तनाव, सीएम भूपेश ने लगाया बड़ा आदोप

रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरक्षण संशोधन विधेयकों पर राज्यपाल की सहमति में कथित देरी को लेकर राजभवन की आलोचना की। उन्होंने कहा कि राजभवन ने राज्य सरकार से सवाल पूछकर अपनी संवैधानिक शक्तियों से बाहर जाकर काम किया है। बघेल ने कहा कि राज्यपाल अनुसुइया उड़िके या तो विधेयकों पर हस्ताक्षर करें या उन्हें राज्य सरकार को लौटा दें। मुख्यमंत्री ने रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में मंगलवार को कांग्रेस के शजन अधिकार महारैलीश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आरक्षण के पक्ष में उनकी सरकार की पहल के बारे में जानकारी दी तथा पिछले महीने विधानसभा द्वारा पारित दो आरक्षण संशोधन विधेयकों को राज्यपाल की मंजूरी में “देरी” को लेकर विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को धेरा.

बघेल ने इस दौरान विपक्षी दल भाजपा पर राजभवन के माध्यम से



छत्तीसगढ़ के लोगों को आरक्षण का लाभ लेने से रोकने की कोशिश करने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ विधानसभा में तीन दिसंबर को छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों,

अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2022 और छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया था। विधेयकों के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजाति को 32 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को 13 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए चार प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

राजभवन और सरकार के बीच बढ़ा तनाव

विधेयकों पर राज्यपाल की सहमति में देरी ने राजभवन और राज्य सरकार के बीच तनाव को बढ़ा दिया है। सभा को संबोधित करते हुए बघेल ने कहा, शशिव्यायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अलग-अलग कार्य हैं और संविधान में उनकी जिम्मेदारियों को परिभाषित किया गया है। राजभवन राज्य सरकार (आरक्षण विधेयकों पर) से सवाल पूछकर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम कर रहा है। संविधान के अनुच्छेद 200 में स्पष्ट उल्लेख है कि या तो राज्यपाल विधेयकों को स्वीकृति देता है या विधानसभा को वापस कर देता है।

अधिकार रोकने की कोशिश

उन्होंने कहा कि विधायकों द्वारा लोगों के हित में विधानसभा में पारित विधेयकों को राजभवन में रोक दिया गया है। बघेल ने कहा, “भाजपा ने राजभवन को राजनीति का अखाड़ा बना दिया है और आरक्षण के लाभ को रोकने की कोशिश कर रही है, जो आपका अधिकार है।” उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने कहा था कि वह विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के एक मिनट के भीतर आरक्षण विधेयकों को मंजूरी दे देंगी, लेकिन एक महीने से अधिक समय हो गया है, विधेयक अभी भी उनकी सहमति के लिए लंबित हैं।



हमने सभी सवालों के जवाब दिए

मुख्यमंत्री ने कहा, “आरक्षण विधेयकों को राज्य के लोगों का समर्थन प्राप्त है। या तो आप (राज्यपाल) इस पर हस्ताक्षर कर दें या इसे (विधानसभा को) लौटा दें। लेकिन वह इनमें से कुछ भी नहीं कर रही हैं और इसके बजाय हमसे सवाल पूछ रही हैं। हमने उनके सभी सवालों का जवाब भी दिया है।” उन्होंने इस दौरान भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर रोजगार छीनने, आरक्षण खत्म करने की कोशिश करने और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बेचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “वे (भाजपा) आरक्षण के खिलाफ हैं और नहीं चाहते कि इसका लाभ लोगों तक पहुंचे。” रैली में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस की राज्य प्रभारी कुमारी शैलजा, राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य तथा पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे।

रायपुर. जगन्नाथ राव दानी शासकीय कन्या उत्कृष्ट हिंदी विद्यालय के मैदान में सरस्वती साइकिल योजना के तहत साइकिल वितरण किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के कक्षा नौवीं के छात्राओं को साइकिल वितरित की गई। इस साइकिल वितरण के आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व मंत्री एवं विद्यायक बृजमोहन अग्रवाल पहुंचे। साथ ही इस कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर निगम के सभापति व पूर्व महापौर प्रमोद दुबे ने की। आयोजित हुए इस कार्यक्रम में सैकड़ों छात्राओं, शिक्षकों के साथ-साथ जिला के शिक्षा अधिकारी श्री ठाकुर, प्राचार्य खंडेलवाल जी व इस क्षेत्र की पार्षद सीमा कंदोई जी मौजूद रही। इस दौरान उन्हें लगभग 300 छात्राओं को मुंह मीठा करा कर साइकिल वितरित की। साथ ही सभी छात्राओं को उज्जवल भविष्य हेतु ढेरों शुभकामनाएं भी दी।

कार्यक्रम के बीच सभी छात्राओं व शिक्षकों को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि, इस साइकिल के मिलने से आप सभी खुश नजर आ रहे हैं। ये सायकिल आप सभी को इसलिए दी गयी है ताकि आप सभी इससे भी दुगनी खुशी से अपनी पढ़ाई को पूरा करें और अपने माता-पिता व शिक्षकों का नाम रोशन करें। साइकिल देने की योजना को आज से बहुत साल पहले शुरू किया गया था, ताकि पढ़ने वाले बच्चे स्कूल जल्दी पहुंच सकें, ज्यादा दूरी को इस साइकिल के माध्यम से तय कर सकें। साथ ही साइकिल को चलाने से बच्चे स्वस्थ रहते हैं और जब वे स्वस्थ रहते हैं तो अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाते हैं।

पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सैकड़ों छात्राओं को बांटी साइकिलें, सभी के चेहरे पर खिली मुस्कान



उन्होंने आगे यह भी कहा कि, बेटा पढ़कर केवल एक घर को आगे बढ़ाता है य जबकि बेटियां अपनी पढ़ाई के माध्यम से दो घरों में शिक्षा के उजियारे को फैलाती हैं। इस उद्देश्य को लेकर कदम उठाए गए, आज परिणाम हमारे सामने हैं कि, मेरिट की सूचियों में लड़कों से भी ज्यादा स्थान लड़कियां प्राप्त करने लगी हैं। इस दौरान बृजमोहन अग्रवाल जी ने विद्यालय की भी तारीफ की और कहा कि, जेआर दानी कन्या विद्यालय हिंदी मीडियम स्कूल होने के बावजूद भी किसी अंग्रेजी मीडियम स्कूल से कम नहीं। आप सभी को गर्व होना चाहिए कि, आप इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं। विद्यालय एक नींव का काम करते हैं, माता पिता अपने बच्चों को 12 साल के लिए इन विद्यालयों व शिक्षकों को सौंप देते हैं। इसी शिक्षा के मंदिर में गढ़े जाते हैं और फिर भविष्य में वे अपने माता-पिता शिक्षकों व मोहल्लों या शहर का नाम रोशन करते हैं। इस दौरान बृजमोहन अग्रवाल ने छात्राओं के साथ साइकिल चलाकर सभी का उत्साहवर्धन भी किया।



सतर्क रहें... आपकी सेहत न बिगाड़ दे बढ़ती सर्दी

रायपुर. राजधानी का तापमान लगातार कम हो रहा है. डॉक्टरों का कहना है कि सर्दियों में हृदयघात, ब्रेन स्ट्रोक और अरथमा के अटैक का खतरा बढ़ जाता है. कई शोध के मुताबिक, ठंड बढ़ने से दिल का दौरा पड़ने का खतरा 50 फीसदी तक बढ़ जाता है.

एम्स के मेडिसन विभाग के प्रोफेसर नवल विक्रम का कहते हैं कि ठंड में शरीर से कम पसीना निकलता है, जिससे शरीर से सोडियम और पानी बाहर नहीं निकलने पर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. इसका असर हृदय को खून पहुंचाने वाली धमनियों पर भी पड़ता है. इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है. एम्स के कार्डियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर अंबुज राय के मुताबिक, दिल की समस्या वाले लोगों के लिए इन दिनों अधिक जोखिम रहता है.

ठंड के दौरान शरीर गर्म होने के लिए अतिरिक्त काम तो करता है, लेकिन इस दौरान हृदय की धमनियों में कोलेस्ट्राल जमने से इसके संकुचित होने की आशंका होती है. ऐसे में हृदय रोगियों को सावधान रहने की जरूरत है.

शरीर से पसीना नहीं निकलना भी बड़ी वजह

एम्स के प्रोफेसर नवल विक्रम ने एक अध्ययन के बावले से बताया कि ठंड में ब्रेन स्ट्रोक का खतरा 30 फीसदी तक बढ़ा जाता है. शरीर से पसीना न निकलने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ना भी ब्रेन स्ट्रोक की बड़ी वजह है. दिमाग तक ऑक्सीजन की जरूरी आपूर्ति नहीं होने से कोशिकाएं मरने लगती हैं. कई मामलों में तो मरीज को पता ही नहीं चलता कि वह ब्रेन स्ट्रोक का शिकार हुआ है.

ये हैं ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण

1. अचानक शरीर के एक भाग में कमजोरी आना.
2. मांसपेशियों का विकृत हो जाना.
3. समझने या बोलने में मुश्किल होना.
4. कम दिखाई देना.
5. चलने में मुश्किल आना, चक्कर आना, संतुलन की कमी हो जाना. अचानक गंभीर सिरदर्द होना.
6. हाथों का सुन्न हो जाना या नीचे की ओर लटक जाना.



दिल के रोगी ये सावधानियां रखें

- ब्लड प्रेशर नियंत्रित रखें. नमक का सेवन कम करें. मक्खन व घी का प्रयोग भी सीमित मात्रा में करें. ब्लडप्रेशर को नियंत्रित रखना और वसा के जमाव का रोकना बेहद जरूरी है.
- इस मौसम में तरल पदार्थ लेते रहें. गुनगुना पानी पिएं.
- व्यायाम बेहद जरूरी है. शरीर से पसीना नहीं निकलेगा तो दिल के दौरे का खतरा अधिक रहेगा.
- तापमान में कमी की वजह से बाहर प्रदूषण अधिक होता है. इसलिए घर में ही व्यायाम करें तो बेहतर है.
- अधिक वसा युक्त चीजें खाना और सिगरेट, शराब आदि का सेवन बिल्कुल न करें. इससे रक्तवाहिनियां संकरी हो सकती हैं और हृदय तक सही रक्तसंचार में समस्या आ सकती है. इसके अलावा दबाव भी बन सकता है.

आपका अपना ORGANIC किणां स्टोर

ORGALIFE®
Eat Organic, Stay Healthy

ORGALIFE®

A WIDE RANGE OF CERTIFIED ORGANIC & ECO FRIENDLY PRODUCTS



*T&C Apply

#Organic किणां स्टोर

FREE
HOME
DELIVERY

(Minimum Order ₹1000)

Order On ► www.orgalife.in Flipkart Amazon

Scan & Shop Now



Shop No.15, Ram Bag Parisar,
Opp, Shri Ram Mandir, VIP Road, Raipur





नई सुविधाएं नए प्रबंधन बेहतर हुआ शहरी जीवन

185

स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट स्कूलों में सभी वर्ग के
1.5 लाख बच्चों को शिक्षा

35 लाख

लोगों को महंगी दवाइयों पर मिली
65 करोड़ रु की राहत

15 लाख से ज्यादा

लाइसेंस व परिवहन सम्बंधित दस्तावेजों की
डाक द्वारा घर पर डिलीवरी

400 यूनिट तक

विजली बिल हाफ

2.5 लाख से अधिक

नए नल कनेक्शन

30% की कमी

रजिस्ट्री गाइडलाइन दरों में

5,000 वर्ग फीट

तक के मकान निर्माण
की सीधी अनुमति



35 लाख से ज्यादा

लोगों का ऑफाइल गलीनिकों
से हुआ मुफ्त इलाज

1 लाख

आवासीय व गैर आवासीय भवनों का
मोर जमीन मोर मकान के अंतर्गत

नियमितीकरण

आवासीय व गैर आवासीय भवनों का

छोटे भू-खण्डों

पर रजिस्ट्री फिर प्राप्तंभ

35,000

लोगों के घर पर पहुंचे शासकीय दस्तावेज

टोल फ्री नं. 14545

पर अब बनेगा पैन कार्ड भी

श्री भूपेश बघेल
मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

R.O. No. - 12270/69

